सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 227, नई दिल्ली । शनिवार, 26 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं...

03 चिड़िया घर ने जानवरों को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए की खास व्यवस्था
06 नोबेल पुरस्कारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव चमका
08 जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोला जॉब मार्केट....

दिल्ली में जल्द बन्द हो सकते है डीज़ल वाहन पर क्यों?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में सभी (राज्य सरकार, परिवहन विभाग, वायु गुणवता आयोग, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी) चाहते है डीज़ल वाहनों पर लग जाए प्रतिबंध। **पर प्रतिबंध क्यों के नाम पर है एक ही जवाब:- प्रदूषण नियंत्रण के प्रति।**

क्या भारत सरकार, दिल्ली सरकार, वायु गुणवता आयोग, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और परिवहन विभाग दिल्ली जनता को यह बता सकते है की आखिर डीज़ल वाहनों पर बंदिश क्यों ?

1. क्या खड़ा वाहन प्रदुषण करता है जो परिवहन विभाग जनता के घरों में प्राइवेट पार्किंग में खड़े वाहनों को बॉक्सर की सेवा से उठवा रहा है ?

2. क्या डीज़ल वाहनों को चलने के लिए प्रयोग होने वाला डीज़लऔर मोबिल ऑयल जो दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध हैं का मानक यूरो VI नहीं हैं ? क्योंकि वाहन से बाहर निकलने वाला धुआं इन्हीं के जलने से उत्पन्न होता है।

3. क्या यूरो VI मानक के पेट्रोलियम पदार्थ के प्रति जनता और उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो घोषणा की गई थी/ है की यूरो VI मानक का डीज़ल पेट्रोल/ सीएनजी के बराबर प्रदूषण प्रदान करता है सही नहीं ?

4. अगर प्रयोग में आने वाला डीज़ल से निकलने वाले धुंए का प्रदूषण पेट्रोल/ सीएनजी के समकक्ष है तो डीज़ल वाहनों पर ही पाबंदी क्यों ?

5. क्या दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और वायु गुणवता आयोग का मानना है कि वाहन चले या नहीं चले या यूरो VI के पेट्रोलियम पदार्थ से चले तो भी वह प्रदूषण करने का जिम्मेदार है ?

6. क्या दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री एवम्-परिवहन मंत्री के साथ आयुक्त परिवहन विभाग बता सकते हैं फिर गलत क्वेरी लगा लगा कर दिल्ली में बिक्री के लिए आए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का क्या कारण है ?

1. इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यवसायिक श्रेणी में जनता को खरीदने नहीं देना

2. डीज़ल वाहन चलने नहीं देने

3. डीटीसी को अपना वाहन लेने नहीं देना

प्रदूषण के नाम पर जनता के वाहनों को उठवाकर अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत और सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड के साथ साथ दिल्ली पिछले साल की ड्राइव में प्राप्त वाहनों के पैसे नहीं देने वाले वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द करने से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में आ जाएगा

क्या दिल्ली में बाहरी राज्यों में जलने वाली पराली का धुआं पाईप लाईन के माध्यम से दिल्ली बोर्डर से अंदर आकर दिल्ली दिल्ली में घूमता है जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है ?

क्या यूरो VI मानक के पेट्रोलियम पदार्थ भी कैलेंडर में दिवाली महोत्सव को आता देख अपने जलने से प्रदूषण छोड़ने लगता है ?

क्या दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा डीज़ल वाहनों के प्रयोग से प्रदूषण नियंत्रण में रहता है जब की उसी वाहन के जनता के पास होने से वह प्रदूषण करता है ?

दिल्ली दिल्ली के अंतर्गत चलने के लिए आम जनता को व्यवसायिक श्रेणी में वाहन चलाने के लिए 2010 से सीएनजी और अब सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य है पर

दिल्ली जल बोर्ड आज भी लोगों को पानी की सप्लाई में डीज़ल वाहनों को प्रयोग में ले रहा है

दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा को अभी अभी जो नए वाहन खरीदकर दिए गए वह भी डीज़ल के। क्या प्रवर्तन शाखा दिल्ली के बाहर जाकर वाहनों की जांच करती है या

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रयोग में लेने वाले वाहनों

दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा प्रयोग में लेने वाले वाहनों

दिल्ली एमसीडी द्वारा दिल्ली में प्रयोग होने वाले डीज़ल वाहन

और

इस बड़े हुए प्रदूषण के समय पर दिल्ली में छिड़काव के लिए प्रयोग आने वाले डीज़ल वाहनो से प्रदूषण नहीं होता पर जनता के वाहनों से प्रदूषण होता है इसीलिए जनता के वाहनों और रोज़गार में प्रयोग होने वाले वाहनों पर रोक लगा दी जाती हैं। कैसा क़ानूनी नियमों वाला फैसला है ना ?

जनता करें तो जुर्माना और जुर्माना लगाने वाला करे तो जरूरत ।

सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर एडवाइजरी जारी, 26-27 अक्टूबर को इन मार्गों पर जानें से बचें

दिल्ली में 26 और 27 अक्टूबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस लाइव म्यूजिक कन्सर्ट के लिए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वह बीपी मार्ग लोधी रोड लाला लाजपत राय मार्ग और जेएलएन स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर जानें से बचें।

नईदिल्ली। पंजाबी पॉप सिंगर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होनेवाले लाइव म्यूजिक कन्सर्ट 'दिल लुमिनाती' को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कन्सर्ट को लेकर ट्रैफिक के डायवर्जन और उसे अलग रूट पर डायवर्ट करने की व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस ने सड़कों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए आज जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एंट्री

कन्सर्ट में आनेवालों को गेट नंबर 2,56,14 और 16 से एंट्री करना होगा।

गेट नंबर 1 और 15 को आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखा जाएगा।

पार्किंग प्लान

जेएलएन स्टेडियम कॉम्पलेक्स, सीजीओ कॉम्पलेक्स, सुनहरी पुल्ला बस डिपो, सेवा नगर बस डिपो और कुश नल्ला में पार्किंग की सुविधा होगी।

सड़क पर प्रतिबंध (शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक)

जेएलएन स्टेडियम रेड लाइट से पूरे बीपी मार्ग पर 26 और 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक आवागमन के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वह बीपी मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग और जेएलएन स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर जानें से बचें।

दिल्ली की सड़कों से जल्द गायब होंगी 5 लाख कारें, 20 हजार जुर्माना लगाने की भी तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली एनसीआर में कार चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार अगर आप चला रहे हैं तो ठहर जाइये। क्योंकि अब इन कारों पर रोक लगने जा रही है। दिल्ली में ऐसी कारों की संख्या करीब 5 लाख है। रोक के बाद भी अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़ जाते हैं तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगेगा।

नईदिल्ली। दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कार चला रहे हैं तो आज से इन्हें छोड़ सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने की आदत डाल लें, क्योंकि परिवहन विभाग जल्द ही इन कारों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है।

यानी कि ग्रैप-तीन के नियम लागू होते ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन चलते पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसा वाहन चलते पाया जाएगा तो उसके मालिक पर 20 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में बीएस-3 के 2,07,038 पेट्रोल वाहन व बीएस-4 के 3,09,225 डीजल वाहन हैं।

दिल्ली में ऐसी कुल पांच लाख कारें पंजीकृत हैं जिनसे लोग दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के आवागमन करते हैं। ये कारें आज से नहीं चल सकेंगी। इन कारों पर प्रतिबंध इसलिए भी लगाया गया है। क्योंकि दिल्ली में कुल होने वाले प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत के करीब है।

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एक नवंबर से दिल्ली में एनसीआर से केवल बीएस-6 श्रेणी वाली बसें ही दिल्ली में आ सकेंगी।

इसके तहत बीएस-3 पेट्रोल यानी एक अप्रैल 2010 से पहले के पेट्रोल वाहन और बीएस-4 डीजल के एक अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत चार पहिया डीजल वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की है। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकारी कार्यों में लगे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे।

क्या है बीएस मानक

बीएस (भारत स्टेज) भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक हैं। जो मोटर वाहन के इंजनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा का निर्धारण करते हैं। मानकों और उनको लागू किए जाने की समयसीमा का निर्धारण पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इन मानकों को पहली बार 2000 में लागू किया गया था।

तब से लगातार मानदंडों को सख्त किया जा रहा है। मानकों के लागू होने के पश्चात निर्मित सभी नए वाहनों के इंजन को इन नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।आसान भाषा में कहें तो बीएस मानक से वाहनों से होने वाले प्रदूषण का पता चलता है, इसके जरिए ही भारत सरकार गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण पर निगरानी करती है।

महंगी पार्किंग का नहीं दिखा खास असर, गाड़ियों की लगी लंबी कतार

बढ़ते प्रदूषण के चलते लागू GRAP के दूसरे चरण में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया है। लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लुटियंस दिल्ली में निजी वाहनों की भरमार है और बाजारों में आने वाले वाहनों की संख्या में कोई कमी नहीं दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बढ़ते प्रदूषण पर कैसे अंकुश लगेगा?

नईदिल्ली। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप का दूसरा चरण लागू हुआ तो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने पार्किंग के दाम तो दोगुना कर दिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है।

लुटियंस दिल्ली में आने वाले निजी वाहनों की भरमार है और कनॉट प्लेस से लेकर खान मार्केट और सरोजनी नगर समेत विभिन्न बाजारों में आने वाले वाहनों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।

ऐसे लोगों की गाड़ियों की संख्या दिख रही ज्यादा

कनॉट प्लेस में दोपहर बाद भी पार्किंग में वाहनों की संख्या खूब दिखी। अन्य बाजारों में ऐसी ही स्थिति हो रही है जिसमें महंगी पार्किंग (Delhi Parking Price Hike) का लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। कनॉट प्लेस समेत दूसरे बाजारों में निजी वाहन लेकर पहुंच रहे ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों के मद्देनजर या तो खरीददारी करने आए हैं या फिर किसी को उपहार आदि पहुंचाने आए हैं।

वहीं, इस मामले में एनडीएमसी के जनसंपर्क विभाग से पक्ष मांगा गया लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। एनडीएमसी के 140 के करीब पार्किंग स्थल हैं। इसमें 94 पार्किंग स्थलों में दो पहिया वाहन खड़े होने की क्षमता 4,454 हैं तो वहीं 2,653 चार पहिया वाहन खड़े हो सकते हैं। जबकि 4,129 चार पहिया वाहनों के खड़े होने की क्षमता दो बहुमंजिला और 12 भागीदारी के तहत चलने वाली पार्किंग में हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में एनडीएमसी को कह रखा है कि जो 50 लाख की गाड़ी लेकर चलता है उसे क्या असर पड़ेगा। पार्किंग के दाम बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जिसको जाना है वाहन लेकर तो वह तो जाएगा। - संजीव मेहरा, अध्यक्ष, खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन

पहले के बराबर ही पार्किंग में आ रही गाड़ियां

कनॉट प्लेस की सभी पार्किंग में शाम को पहले जैसी ही स्थिति दिख रही है। कनॉट प्लेस में एक पार्किंग संचालित करने वाले एक कर्मी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि पार्किंग के दाम बढ़ने से मुश्किल हो रही है क्योंकि जब लोग प्रवेश या निकास करते हैं तो दाम बढ़ने पर बहस करते हैं।

फिर लोगों को समझाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वाहनों की संख्या में कमी नहीं आई है पहले भी दिनभर में 300 के करीब गाड़ी आती थी अब भी उतनी ही आ रही है।

एनडीएमसी पहले दो पहिया वाहनों से 10 रुपये प्रति घंटा शुल्क लेती थी, मंगलवार को इसे बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिघंटा कर दिया। चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति घंटा कर दिया गया है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

छोटे ट्रांसपोर्टर्स की डूबती रोजी-रोटी: सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग

छोटे ट्रांसपोर्टर्स ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

- टोल टैक्स में 30% कटौती की मांग, लागत वसूल चुके टोल - प्लाजाओं की हो जांच
- ऑनलाइन चालान प्रक्रिया पर रोक, ड्राइवर की उपस्थिति अनिवार्य करने का सुझाव
- देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एकरूपता और 30% की कमी की अपील
- दो महीने बाद देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की रोजी-रोटी पर संकट

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली: देशभर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े छोटे कारोबारियों और सिंगल मोटर मालिकों की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। इसके चलते हजारों परिवार भूखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। इस विकट स्थिति को देखते हुए, देश के छोटे ट्रांसपोर्टर्स और सिंगल मोटर मालिकों के संगठन दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के महासचिव श्याम सुन्दर ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य रूप से हम तीन प्रमुख मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे है। प्रेस वार्ता में दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के अध्यक्ष हरीश ग्रोवर, सचिव दिनकर सिंह, कोषाध्यक्ष वेदप्रकाश एवं एडवोकेट डॉ चंद्रा राजन, एडवोकेट चरणजीत सिंह, डीसी कपिल आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

श्याम सुंदर ने कहा कि पहला, छोटे ट्रांसपोर्ट्स की प्रमुख समस्याओं में टोल टैक्स एक बड़ी चुनौती बन गया है। संगठन की मांग है कि देशभर में टोल टैक्स की दरों को कम से कम 30% घटाया जाए। इसके अलावा, उन टोल प्लाजाओं की जांच की जाए, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है। ऐसे टोल प्लाजा तुरंत बंद किए जाने चाहिए। इससे छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनका व्यवसाय पुनर्जीवित हो सकेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा देशभर में ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया से जुड़ा है। श्याम सुंदर ने बताया कि संगठन का मानना है कि ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ द्वारा चलती गाड़ियों की फोटो खींचकर और टोल प्लाजाओं से जानकारी लेकर जो चालान किया जाता है, वह छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए अत्यधिक बोझ साबित हो रहा है। उनका कहना है कि चालान प्रक्रिया में सुधार किया जाए और चालान केवल तब हो जब मौके पर ड्राइवर मौजूद हो। इससे व्यवसायियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। और तीसरी प्रमुख मांग पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों से संबंधित है। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें समान होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न दरों का अतिरिक्त भार न पड़े। इसके अलावा, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30% की कटौती की जाए, ताकि व्यवसायियों को कुछ राहत मिल सके और वे अपने कारोबार को सुचारु रूप से चला सकें।

उपरोक्त मुद्दों को लेकर दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच द्वारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में व्याप्त संकट और समस्याओं को लेकर एक विशेष अपील-पत्र राष्ट्रपति महोदया और संबंधित सरकारों के समक्ष पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रेस वार्ता के जरिये भारत सरकार और राज्य सरकारों से तत्काल इन तीन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और उचित कदम उठाने की मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकारें इन मांगों को शीघ्रता से नहीं मानतीं, तो दो महीने बाद देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यह आंदोलन न सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए होगा, बल्कि देश के हर उस व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जो किसी न किसी रूप में वाहनों का इस्तेमाल करता है।

गुजरात के सालंगपुर हनुमानजी मंदिर परिसर मे 1100 कमरों वाला गोपालानंद स्वामी यात्रिक भुवन बनकर तैयार

गुजरात के सालंगपुर में गोपालानंद स्वामी यात्रिक भुवन बनकर तैयार हो गया है। इस यात्रिक भुवन का उद्घाटन 31 अक्टूबर को माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के हाथ होगा। इस यात्रिक भुवन का निर्माण किसी सेवन-स्टार होटल से कम नहीं है। यहां जानें इस आलीशान यात्रिक भुवन से जुड़ी सभी बातें और यहां यात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। आइए जानें।

सालंगपुर हनुमानजी मंदिर के परिसर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से दुनिया के किसी भी आध्यात्मिक स्थान और गुजरात में पहला सबसे ज्यादा 1100 कमरों वाला गोपालानंद स्वामी यात्रिक भुवन बनकर तैयार हो गया है। इस 8 मंजिला गेस्ट हाउस का उद्घाटन 31 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमितभाई शाह और परम पूज्य धर्मधुरंधर 1008 आचार्यश्री राकेशप्रसादजी महाराज और वडताल गादी के संत करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री हरिप्रकाश स्वामी के दृढ़ संकल्प और कोठारी स्वामी श्रीविवेकसागरदासजी के मार्गदर्शन और वडताल मंदिर बोर्ड के सहयोग से इस राजमहल जैसे गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन का निर्माण किया गया है।

दादा के दर्शन के लिए सालंगपुर में दिन-ब-दिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन का निर्माण मंदिर के संतों ने सेवन स्टार होटल की टक्कर में कराया है ताकि दादा के भक्तों को कोई परेशानी न हो। यह गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन श्रीकष्टभंजन देव हनुमानजी मंदिर के बाईं ओर थोड़ी दूरी पर और नए भोजनालय के ठीक पीछे बना है। इस 20 बीघा की भूमि में बने यात्रिक भवन की भव्यता अद्भुत है। यह भवन 9,00,000 वर्ग फुट में बनाया गया है। यह इमारत 8 मंजिलों वाली है और 108 फीट ऊंची है और 340 कॉलम पर खड़ी की गई है।

राजमहल जैसी दिखने वाली इस इमारत का एलिवेशन इंडियन रोमन शैली का है। इस बिल्डिंग की डिजाइन चार से पांच बार बनाई गई। उसके बाद संतों द्वारा वर्तमान डिजाइन को फाइनल किया गया। भवन में प्रवेश करते समय इन-आउट के लिए दो रैंप बनाए गए हैं। जहां से हमने एक रिसेप्शन एरिया बनाया है, जिसमें प्रवेश करने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लाउंज हो। यहां से यात्री मिनटों में कमरा बुक कर सकते हैं। यात्रियों के लिए कुल 1000 से अधिक कमरे उपलब्ध हैं। जिसमें 500 एसी और 300 नॉन एसी कमरे, 5 सर्वेंट हॉल और 14 स्टोर रूम शामिल हैं। सीढ़ियों के अलावा यहां 10 हाई स्पीड एलिवेटर (लिफ्ट) भी हैं ताकि यात्री आराम से अपने कमरे तक जा सकें।

गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन में एक कमरे में पांच लोग, यानी 1000 से ज्यादा कमरों में 5,000 से अधिक लोग आराम से रह सकते हैं। इस बिल्डिंग में 400 एसी कमरों का मेंटेनेंस किराया 1500 रुपये और 300 नॉन एसी कमरों का 800 रुपये होगा। जिसमें हर कमरे में चार सिंगल बेड और एक गद्दा, रजाई और तकिया और एक कुर्सी भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 45 स्युट में प्रति रूम का मेंटेनेंस किराया 3 हजार रुपए होगा। प्रत्येक कमरे में 4 सिंगल बेड और एक डबल बेड, फर्नीचर के साथ मेज और कुर्सी होगी।

गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन में हर मंजिल पर 6-6 वॉटर डिस्पेन्सर एवं कॉमन टॉइलेट-बाथरूम की भी व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन की व्यवस्था की गई है। इस कैंटीन का आकार 12 हजार वर्ग मीटर है, जिसमें 200 लोग अपने खर्चे पर नाश्ता कर सकेंगे। खास बात यह है कि श्रद्धालु और तीर्थयात्री नूतन भोजनालय में निःशुल्क नाश्ता और भोजन प्रसाद ले सकेंगे। लगभग पूरी बिल्डिंग का फर्श मशीन से साफ होगा। इस भवन में एक कपड़े धोने का कमरा भी बनाया गया है। इमारत का संचालन 100 लोगों के स्टाफ द्वारा किया जाएगा।

गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन में 300 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहां की पार्किंग भी काफी बड़ी है। जिसमें 2500 से ज्यादा कारें, 1 हजार दोपहिया वाहन और 50 बसें आराम से पार्क की जा सकती हैं। ये पार्किंग स्थल इमारत के दोनों ओर बनाए गए हैं।

श्री हरिप्रकाश स्वामीजी ने गोपालानंद स्वामी यात्रिक भुवन के बारे में कहा, "विश्व और गुजरात के आध्यात्मिक जगत का सबसे विशाल 1100 कमरों वाला गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन सालंगपुर में बनकर तैयार हो गया है। जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2024 को माननीय गृह मंत्री श्रीअमितभाई शाह, वडताल गादी आचार्य राकेश प्रसादजी महाराज, वरिष्ठ संत और वडताल मंदिर बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

हरिप्रकाश स्वामी ने गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन के डिजाइन के बारे में विशेष रूप से कहा कि, "गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन के डिजाइन में वैदिकता और वैज्ञानिकता का मिलित तर्क है। पहली तितली की विशेषता यह है कि यह शांति का प्रतीक है, यह कभी किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करती। तितली की एक और विशेषता यह है कि वह प्रकाश की पुजारी है, तितली प्रकाश की ओर आकर्षित होती है, अंधेरे की पुजारी नहीं। तितलियों की तीसरी विशेषता है की वह सुगंध के चाहक होती हैं। चौथी तितली की खासियत यह है कि यह बेहद खूबसूरत होती है। तितली बहुत सुंदर है, भगवान ने इसे बहुत उत्तम बनाया है। तितलियों किसी को परेशान नहीं करती, तो हमने ऐसा सोचा, गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन में जो भी भक्त आएगा, उसको प्रकाश मिले, शांति मिले, सुगंध मिले, क्योंकि दादा के दरबार में कभी अंधकार या अंधविश्वास का पुजारी नहीं होगा। दादा के दरबार में वही लोग आते हैं जिनके मन में आस्था, विश्वास, आत्मनिष्ठा, श्रद्धा और भक्ति होती है। मैं गारंटी देता हूं कि दादा के दरबार में हर कोई भरोसेमंद है।"

दिवाली 2024 : अब डायबिटीज के कारण नहीं मारना पड़ेगा मन, ये 5 मिठाइयां करेंगी आपकी स्वीट क्रेविंग को शांत

बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। रोशनी का यह पर्व इस बार 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। फेस्टिव सीजन तो मिठाइयों के बिना अधूरा ही माना जाता है लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज (Diwali sweets for diabetics) हैं तो मीठा सोच-समझकर ही खाना चाहिए। ऐसे में आप मिठाई के ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।

दीवाली का त्योहार अब बेहद नजदीक आ चुका है। साल का यह समय बेहद खुशनुमा होता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दौरान पूरे देश में उत्सव का माहौल रहता है। रोशनी का यह पर्व हर साल काफी धूमधाम से मनाया जाता है। फेस्टिव सीजन के दौरान खानपान का भी अपना अलग मजा होता है। कई तरह के पकवान और ढेर सारी मिठाइयां अक्सर त्योहारों का मजा दोगुना कर देती हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो फेस्टिव सीजन में अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है, जिसका को इलाज नहीं है। इसे आमतौर पर खानपान और दवाओं की मदद से मैनेज किया जाता है। ऐसे में अक्सर फेस्टिव सीजन के दौरान अपने खानपान का खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ढेर सारी मिठाइयों को देख और त्योहार के सीजन में अक्सर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी एक डायबिटीज पेशेंट हैं, तो ये मिठाइयों के ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।

बादाम के लड्डू

बादाम के आटे से तैयार लड्डू डायबिटीज में काफी फायदेमंद साबित होंगे। बादाम ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर करने में मदद करता है। ऐसे में आप बादाम के आटे, घी और स्टीविया या गुड़ जैसे नेचुरल स्वीटनर का उपयोग कर इन्हें आसानी से घर पर बना सकते हैं और फेस्टिव सीजन में अपनी मीठे की क्रेविंग को शांत कर सकते हैं।

नारियल की बर्फी

आप दीवाली के मौके पर स्वादिष्ट और हेल्दी नारियल की बर्फी भी ट्राई कर सकते हैं। बिना झंझट बनने वाली इस मिठाई को बनाने के लिए सूखे नारियल, कंडेंस्ड मिल्क और बेहद कम मीठे का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो शुगर अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है।

खजूर और नट्स के लड्डू

खजूर नेचुरल शुगर का एक बेहतरीन विकल्प है, जो किसी भी डिश को नेचुरल मिठास देता है। ऐसे में दीवाली के लिए खजूर और नट्स के लड्डू एक बढ़िया ऑप्शन साबित होंगे, जो पोषण से भरपूर होने की वजह से फायदेमंद भी होंगे। एनर्जी से भरपूर यह लड्डू रिफाइंड शुगर से बचाते हैं।

गुड़ और सूजी का हलवा

अगर आप परिवार में भी कोई डायबिटीज का मरीज है, तो दीवाली के मौके पर आप उनके लिए गुड़ और सूजी का हलवा बना सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, सामान्य तरीके से सूजी का हलवा बनाएं और इसमें चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ग्लूकोज कंट्रोल करने में मदद करता है।

डार्क चॉकलेट मूस

डार्क चॉकलेट (कम से कम 70% कोको), कोकोनट क्रीम और वेनिला के मिश्रण से बना यह मूस कम कार्ब्स के साथ एक शानदार स्वाद प्रदान करता है। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसका ब्लड शुगर पर कम प्रभाव पड़ता है।

कविता

हँसी स्वयं मुस्कुरा के शरमाई है

आज तो एक पोस्टर ने धूम मचाई है।
उसे देखकर ही सबको हँसी आई है।
चारा घोटाले से पड़ा था उनका पाला।
ईडी-सीबीआई ने उन्हें निचोड़ डाला।
जो था सामाजिक न्याय का रखवाला।

आज तो एक पोस्टर ने धूम मचाई है।
उसे देखकर ही सबको हँसी आई है।
हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क,
बनाने का इन्होंने किया था तब वादा।
समोसे में ही आलू हो गए थे ज्यादा।

आज तो एक पोस्टर ने धूम मचाई है।
उसे देखकर ही सबको हँसी आई है।
भई खूब पसंद था इन्हें मंत्रालय रेल।
मंजूर कुछ और था तो हो आए जेल।
अब एक अलग ही मची है रेलम पेल।

आज तो एक पोस्टर ने धूम मचाई है।
उसे देखकर ही सबको हँसी आई है।
इनके बड़े जबरदस्त फैन है कार्यकर्ता।
बिना सोचे ही फरमा रहे रफ्ता-रफ्ता।
उन्हें भारतरत्न देने की मांग दोहराई है।
आज हँसी स्वयं मुस्कुरा के शरमाई है।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

क्या आप भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को मानते हैं एक, तो यहां समझें दोनों में अंतर

दिल से जुड़ी समस्याओं के मामले तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन दिनों कम उम्र में ही लोग दिल से जुड़ी कई समस्याओं की चपेट में आ रहे हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इन्हीं में से एक है जिनके मामले आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि कई लोगों को इन दोनों में अंतर नहीं पता है। ऐसे आज जानेंगे क्या है दोनों में अंतर।

इन दिनों दिल से जुड़ी समस्याएं तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। आए दिन सशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आती हैं, जिसमें लोगों की अचानक हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक की वजह से जान चली जाती है। हार्ट संबंधित बीमारियों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं सभी सुनने में लगभग एक जैसी लगती हैं।

हालांकि, दिल से जुड़ी इन समस्याओं का हर एक टर्म का अपना अलग मतलब है, जिसकी सही जानकारी होना जरूरी है। सबसे अधिक दुविधा होती है, जब बात हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की आती है। कुछ लोग दोनों ही टर्म को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग दो बातें हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर-

क्या है हार्ट अटैक?

हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्कशन भी कहते हैं।

ये ब्लड सर्कुलेशन में पैदा होने वाली समस्या है।

जब हार्ट में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, तो ये हार्ट अटैक कहलाता है।

हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है।

अगर इस ब्लॉक को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो हार्ट का वो हिस्सा निष्क्रिय होने लगता है, जिस हिस्से को वो आर्टरी ब्लड पहुंचाने का काम करती है।

इसके लक्षण हैं, सीने में दर्द, उल्टी, मितली, पसीने आना, सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत आदि।

इस दौरान इंसान जिंदा रहता है और संभवतः होश में रहता है लेकिन तत्काल मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है।

कार्डियक अरेस्ट क्या होता है?

कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल समस्या है।

हार्ट में इलेक्ट्रिकल मालफंक्शन के कारण हार्टबीट अनियमित (कार्डियक एरिथमिया) हो जाती है जिससे कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर होता है।

ऐसे में हार्ट का पंपिंग एक्शन प्रभावित होता है। इसलिए हार्ट ब्रेन,लंग्स और अन्य अंगों तक ब्लड नहीं पहुंचा पाता है।

कुछ ही सेकंड में पल्स धीमी होने लगती है और व्यक्ति बेहोश हो सकता है।

इसके लक्षण हैं बेहोश होना, रिस्पॉन्स न देना, असामान्य तरीके से सांस लेना, चेहरा नीला पड़ना, पल्स कम होना आदि।

ये एक अर्जेंट मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान बेहोश हो जाता है, सांस और पल्स गायब होने लगती है और ऐसे में तत्काल सीपीआर, हॉस्पिटल और एक्सपर्ट की जरूरत होती है।

पुरानी हुई दूध वाली चाय, अब सेहतमंद रहना है तो आज से भी पीना शुरू कर दें घी वाली चाय

दूध वाली चाय तो सभी ने पी होगी। यह चाय लवर के लिए एक परफेक्ट ड्रिंक है लेकिन इसे पीने से सेहत को कई नुकसाम भी होते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए है दूध वाली चाय का एक बेहतरीन ऑल्टरवेटिलव जो आपकी सेहत के लिए काफी गुणकारी है। हम बात कर रहे हैं Ghee Tea की। आइए जानते हैं इसे पीने के फायदे।

सुबह-सुबह सो कर उठते ही बेड टी या कॉफी की आदत को एक बुरी आदत माना जाता है। इसे हेल्दी नजरिया देने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट घी कॉफी लेकर आए, जिसके अपने कई फायदे हैं। घी एक गुड फैट है, जो कि शरीर के लिए फायदेमंद है। लेकिन अब हाल ही में एक नया ट्रेंड आया है, जिसकी वजह से लोगों ने घी कॉफी से मूव ऑन करना शुरू कर दिया है और वो है घी टी यानी घी वाली चाय।

हालांकि, ये एक पुरानी आयुर्वेदिक रेसिपी है जिसके ढेरों फायदे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय अब लोगों के बीच इसका चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में घी वाली चाय से होने वाले इसी फायदे के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं घी वाली चाय और क्या है इसके फायदे-

घी वाली चाय बनाने का तरीका

एक कप उबलते पानी में चायपत्ती डालें।

ब्लेंडर में एक टेबलस्पून घी डालें। ध्यान रहे कि घास खाई हुई गाय के दूध से बने देशी घी का सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

घी के साथ केसर की दो लड़ियां (वैकल्पिक) डालें। ये स्किन के लिए बेहतरीन है, जिसमें जीरो कार्ब्स हैं और ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी माना जाता है।

चायपत्ती के साथ उबले हुए पानी को ब्लेंडर में छानें और सभी चीजों को ब्लेंड करें। ब्लेंड करने से चाय थोड़ी फ्रोथी बनती है।

बिना ब्लेंडर के भी घी वाली चाय आसानी से बनाया जा सकता है। पानी में चायपत्ती डाल कर उबालें और कप में छान लें। फिर एक टेबलस्पून घी डाल कर मिक्स करें।

तैयार है घी वाली चाय, इसे गर्मागर्म सर्व करें।

घी वाली चाय के फायदे

स्किन हेल्थ में सुधार- विटामिन ए से भरपूर घी वाली चाय कॉलेजन प्रोडक्शन में मदद करती है, जिससे स्किन हेल्थ में सुधार होता है और एजिंग की प्रक्रिया धीमी होती है।

जोड़ों के दर्द में आराम- घी एक नेचुरल लुब्रिकेंट है, जिससे हड्डियों और जोड़ों में ये लुब्रिकेंट का काम करता है और दर्द से राहत दिलाता है।

वेट लॉस- घी चाय पीने से पेट भरे होने का एहसास होता है, जिससे क्रेविंग कम होती है और वेट लॉस में मदद मिलती है।

पाचन क्रिया में सुधार- घी वाली चाय कब्ज और IBS जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। इससे गट हेल्थ अच्छी बनी रहती है।

इम्युनिटी मजबूत बनाए- घी और चाय दोनों में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट इम्युनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं।

डेंगू से ज्यादा मलेरिया और चिकनगुनिया फैला रहे आतंक, चौंकाने वाले हैं दिल्ली के आंकड़े

दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या जरूर कम है लेकिन मलेरिया और चिकनगुनिया की बढ़ोतरी ने निगम की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मलेरिया के मरीजों की संख्या दोगुना तो वहीं पर चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या तीन गुणा रफ्तार से बढ़ रही है। खबर के माध्यम से पढ़िए इनके फैलने के लक्षण क्या हैं और बीते पांच सालों में इनकी संख्या किस कदर बढ़ी है।

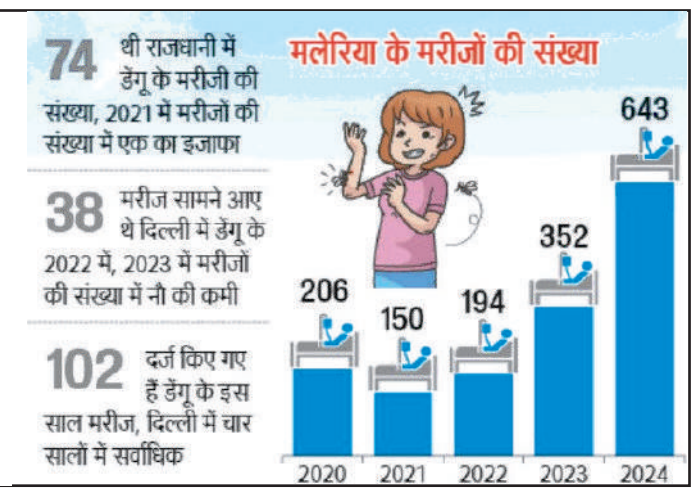

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बीते वर्षों की तुलना में डेंगू के मरीजों की संख्या तो कम हैं लेकिन निगम की परेशानी मलेरिया और चिकनगुनिया के बढ़ रहे मरीज है। ऐसा नहीं है कि मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या एक दो ज्यादा बल्कि मलेरिया के करीब बीते वर्ष से ज्यादा दोगुने मरीज सामने आ रहे हैं और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या तीन गुणा ज्यादा है।

हालांकि राहत की बात है कि डेंगू के मुकाबले मलेरिया और चिकनगुनिया में जान का खतरा कम रहता है लेकिन मरीज को बुखार और बदन दर्द के साथ जोड़े के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। इस वर्ष क्या है अब तक मच्छरजनित बीमारियों को लेकर क्या है मरीजों की स्थिति पेश हैं निहाल सिंह की रिपोर्ट...

ऐसे होता है मलेरिया

मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर (female anopheles mosquito) के काटने से होता है। ये मच्छर गंदे पानी में पनपता है। आमतौर पर मलेरिया के मच्छर रात में ही ज्यादा काटते हैं। कुछ मामलों में मलेरिया अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। ऐसे में बुखार ज्यादा न होकर कमजोरी होने लगती है और एक स्टेज पर मरीज में खून की कमी हो जाती है।

ऐसे होता है डेंगू

एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है। डेंगू के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार साधारण डेंगू बुखार होता है। पांच से सात दिन तक बुखार रहने पर मरीज आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरा डेंगू का बुखार रक्तस्रावी बुखार होता है।

इसमें रक्त वाहिकाओं में रक्तस्राव होता है और खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगती है। तीसरा प्रकार डेंगू शाक सिंड्रोम होता है। इसमें बुखार कई दिनों तक रहता है। जिसमें तेज बदन दर्द होता है।

चार साल में कार्रवाई

विवरण	2021	2022	2023	2024
कितने घरों में पाया मच्छरों का लार्वा	1,62,349	1,51,386	2,97,074	2,56,411
कानूनी नोटिस भेजे गए	1,27,009	1,07,099	1,54,218	1,44,658
कितने लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई	19,172	41,904	68,238	49,982
कितने लोगों के चालान काटे गए	6,880	15,821	24,511	11,409

मच्छर जनित बीमारियों के लक्षण

तेज और लगातार बुखार
तेज बदन दर्द
प्लेटलेट्स का गिरना
नाक मुंह से खून बहना
ठंड लगना और बुखार आना

इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बीमार होने की संभावना हो जाएगी कम

घर में सजावटी पौधों के गमलों में पानी तीन से चार दिन में बदलते रहे

कूलर को साफ रखें और उसका पानी भी तीन से चार दिन में बदलते रहे

छत पर टूटे हुए कप प्लेट, खुले डब्बे गमले आदि में पानी जमा न होने

पानी की टंकी को ढककर रखें

पानी के कंटेनर में पानी इकट्ठा रखें तो ढककर रखें, नहीं तो चार दिन में उसे खाली करते रहे

विंडो एसी से पानी निकलता है तो वह किसी बर्तन या छत पर इकट्ठा न हो ऐसी व्यवस्था रखें

पूरी बाजू के कपड़े पहन कर रखें। पार्क में जाए तो पूरी बाजू के कपड़ो के साथ जूते व जुर्राब व पैरो तक बदन को ढके रखें

इस वर्ष दिल्ली में निकाय अनुसार डेंगू-मलेरिया व चिकनगुनिया के मरीजों की स्थिति

निकाय	डेंगू	मलेरिया	चिकनगुनिया
एमसीडी	2945	630	100
दिल्ली कैंट	82	09	02
एनडीएमसी	36	02	00
अपुष्ट पते	1206	161	64
रेलवे	19	02	00
अन्य राज्य	189	51	09

नोटः सभी आंकड़े प्रत्येक वर्ष एक जनवरी से लेकर 19 अक्टूबर तक के हैं।

अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमले की कोशिश, AAP ने BJP पर लगाया आरोप; भाजपा की आई प्रतिक्रिया

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमले की कोशिश हुई। आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोगों ने विकासपुरी में केजरीवाल पर हमला किया। पुलिस ने भाजपा के लोगों को नहीं रोका। सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल पर हमला होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान उन पर भाजपा द्वारा हमला की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान भाजपा के लोगों ने हमला किया है। आप ने कहा कि भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे। पुलिस ने भाजपा के लोगों को नहीं रोका।

बीजेपी केजरीवाल को मारना चाहती है: CM आतिशी

दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ₹दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि बीजेपी की गंदी राजनीति किस हद तक गिर सकती है। अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी पदयात्रा के दौरान बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। बीजेपी जानती है कि वह AAP और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती, इसलिए वह ऐसी गंदी राजनीति पर उतर आई है और अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है।"

भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया: सिसोदिया

पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "अरविंद केजरीवाल पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा पर होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी।"

उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने पहले जेल में मारने की कोशिश की। अब कोर्ट ने उन्हें रिहा किया है और वो अपनी दिल्ली की जनता से मिलने रोज़ बाहर निकल रहे हैं तो भाजपा उनको अपने गुंडों द्वारा मारने की कोशिश कर रही है। भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से ख़त्म करना चाहती है क्योंकि उनको चुनावों में वो कभी नहीं हरा पायेंगे।₹

भाजपा ने हमला करने की कोशिश की: संदीप पाठक

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, "भाजपा ने अपने गुंडे भेजकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने की कोशिश की। जिस तरह से लोग उन्हें समर्थन और प्यार दे रहे हैं, वह भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले इन्होंने केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश की और अब ये सब कर रहे हैं। जो मर्जी कर लें, ये लोग अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते।"

चिड़िया घर ने जानवरों को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए की खास व्यवस्था, प्रदूषण से बचाने के लिए भी हुआ इंतजाम

सुषमा रानी

दिल्ली चिड़ियाघर ने जानवरों को ठंड और प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जानवरों के लिए विशेष आश्रय लकड़ी के तख्त चटाई बांस की स्क्रीन हवा को रोकने के लिए छप्पर रूम हीटर और डीह्यूमिडिफायर लगाए गए हैं। शाकाहारी जानवरों और पक्षियों को गर्म रखने के लिए धान के भूसे का बिस्तर और विशेष रूप से तैयार किए गए आश्रय दिए जाएंगे।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) ने जानवरों को वायु प्रदूषण के साथ-साथ ठंड से बचाने के लिए भी कवायद शुरू कर दी है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, चिड़ियाघर के अधिकारी जानवरों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे है, साथ ही चिड़ियाघर परिसर में प्रदूषण को कम करने के प्रयास भी कर रहे हैं।

चिड़ियाघर प्रबंधन ने जानवरों की ठंड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत शीतकालीन प्रबंधन योजना तैयार की है। विभिन्न प्रजातियों के अनुसार और उम्र के हिसाब से ये रणनीतियां लागू की जाएंगी, जो ठंड में जानवरों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

जानवरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आश्रय

चिड़ियाघर के अधिकारी ने बताया कि जानवरों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आश्रय, लकड़ी के तख्त, चटाई, बांस की स्क्रीन, हवा को रोकने के लिए छप्पर, रूम हीटर और डीह्यूमिडिफायर लगाए जाएंगे।

शाकाहारी जानवरों और पक्षियों को गर्म रखने के लिए धान के भूसे का बिस्तर और विशेष रूप से तैयार किए गए आश्रय दिए जाएंगे, जबकि मांसाहारी और प्राइमेट को ठंडी सतह से बचाने के लिए लकड़ी के तख्त, चटाई और कंबल दिया जाएगा।

कमजोर जानवरों की सुरक्षा के लिए नर को रखा जाएगा अलग

चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि कमजोर जानवरों की सुरक्षा के लिए मणिपुरी हिरण जैसी प्रजातियों में प्रमुख नर जानवर को एक-दूसरे से अलग किया जाएगा, क्योंकि इस सर्दियों के माह में इनके बच्चे पैदा होते हैं और अलग रखने से इनमें होने वाले संघर्ष को रोका जा सकेगा व नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

आहार में नट्स, गुड़ और गन्ना शामिल किया गया

इसके साथ ही जानवरों के आहार में भी बदलाव किया जाएगा। जानवरों के आहार में नट्स, गुड़ और गन्ना शामिल किया गया है, उनको पोषक तत्वों की खुराक और इम्यूनोबूस्टर भी दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सर्दियों के मौसम में होने वाली किसी भी स्वास्थ्य समस्या को तुरंत दूर करने के लिए पशु चिकित्सा प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी जानवरों को जरूरत पड़ने पर समय पर चिकित्सा सहायता मिले।

मूवी रिव्यू : नवरस कथा कोलाज

अद्भुत, बेहतरीन और एक संदेश देती फिल्म

रेटिंग , 4 ****

आप किसी हस्ती के साथ मिलने "या अपना कोई प्रस्ताव रखने से पहले सौ बार सोचते है कि मेरे प्रस्ताव में इतना दम खम है कि अपना प्रस्ताव किसी बड़ी हस्ती के सामने रखूं लेकिन इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एप्रोच किया कि वह इस फिल्म को देखे , क्योंकी इस फिल्म में कई ज्वलंत सामाजिक और महिलाओं पर शोषण के मुद्दे पूरी ईमानदारी के साथ पेश किए गए हैं।

मुझे अहसास हुआ कि यह फिल्म चालू बॉक्स ऑफिस मसाला फिल्मों से दूर हैं ।

निर्देशक और इस हीरो प्रवीण हिंगोनिया ने अपनी इस फ़ल्मि में नौ अलग अलग किरदार निभाकर कमल हासन और संजीव कुमार को ट्रिब्यूट पेश किया है। फिल्म 'नया दिन नई रात' में संजीव कुमार ने नौ रोल तो कमल हासन ने फिल्म दशावतारम में दस क़िरदार निभाए थे।

चंबल इंटरनेशनल फ़ल्मि फेस्टिवल में इस फिल्म को तीन अवार्ड मिले जिनमें बेस्ट फीचर फिल्म, सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस रेवती पिल्लई और सपोर्टिंग ऐक्टर स्वर हिंगोनिया को दिया गया। स्वरध्रुपद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फ़ल्मि को प्रवीण हिंगोनिया के साथ एसकेएच पटेल ने प्रोड्यूस किया है

इस मौके पर चंबल इंटरनेशनल फ़ल्मि फेस्टिवल में नवरस फ़ल्मि को तीन अवार्ड मिले जिनमें बेस्ट फीचर फिल्म, सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस रेवती पिल्लई और सपोर्टिंग ऐक्टर स्वर हिंगोनिया को दिया गया। स्वरध्रुपद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फ़ल्मि के सह निर्माता अभिषेक मिश्रा हैं।

करीब ढाई घंटे की इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म के मेकर को सैल्यूट किया कि उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग कश्मीर से लेकर मोहब्बत की नगरी आगरा तक की ऐसा कोई नामी बैनर भी नहीं कर पाता । फिल्म में पांच गीत है और सभी गीतों में एक अलग संदेश हैं।

मेरी नजर में यह एक ऐसी फ़ल्मि बनी है जिसके मेकर चाहते है कि समाज मे कुछ परिवर्तन आए, युवा पीढ़ी को कुछ सीखने के लिए बाध्य करे।

अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस फ़ल्मि के लिए हर किसी ने बहुत तैयारी की । फिल्म के टाइटल से आप समझ सकते है फिल्म में अलग अलग रस की नौ कहानियां है। सो हम इन अलग अलग स्टोरीज पर बात न करके फिल्म पर बात करते है।

अक्सर मुंबई के टॉप बैनर भी फिल्म रिलीज से पहले दिल्ली मुंबई या एक आध और बड़े सिटी में आते है अपनी फ़ल्मि का प्रोमोशन करके निकल जाते है लेकिन इस फिल्म को कई छोटे बड़े शहरों में पूरी टीम ने प्रमोट किया

एक अनुभवी क्रिटिक के नजरिए से फिल्म को देखूं तो फिल्म में कई कमियां है इसका बड़ा कारण फिल्म का सीमित बजट ही रहा। इसलिए इन्हें नजरअंदाज करके देखा जाए तो बस एक शब्द काफी है अद्भुत फिल्म

आप अकेले नहीं आपके अपनो दोस्तो के साथ फिल्म देखने जाए,हां ऐसी फिल्मों से सिनेमा मालिक कन्नी काटते है तो कोई बात नहीं नजदीकी नहीं तो कुछ दूर इस फिल्म को देखकर आए, कुछ हासिल करके ही हाल से बाहर आयेंगे

काश , ऐसी साफ सुथरी फिल्म को देश की सभी सरकार रिलीज से पहले टैक्स फ्री करे, दूरदर्शन पर दिखाए।।।

कलाकार : प्रवीन हिंगोनिया, , दयानंद शेट्टी, रेवती पिल्लई सुनीता महेश शर्मा , प्राची सिन्हा, अमरदीप झा , श्रेया, जय शंकर त्रिपाठी और स्वर हिंगोनिया।

सुषमा रानी

नेटफ्लिक्स, ALTT और X (पूर्व में ट्विटर) के खिलाफ यौन सामग्री प्रसारित करने के मामले में मुकदमे दर्ज

सुषमा रानी

- x उदय महुरकर ने यौन सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और 10-20 साल की सजा तथा कम से कम तीन साल तक जमानत न देने वाले कड़े कानूनों की मांग की।
- x पीओसीएसओ अधिनियम, आईटी अधिनियम, महिलाओं के अशोभनीय चित्रण (निषेध) अधिनियम, और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के उल्लंघनों का हवाला दिया गया।
- x सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित यौन सामग्री 2047 तक भारत के एक महान राष्ट्र बनने के लक्ष्य को बाधित कर सकती है।

नई दिल्ली। सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक श्री उदय महुरकर ने नेटफ्लिक्स, ALTT और X (पूर्व में ट्विटर) के खिलाफ यौन स्पष्ट सामग्री प्रसारित करने के आरोप में कानूनी कार्यवाही शुरू की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माहूरकर ने गेम्स ऑफ बॉलीवुड के संस्थापक संजीव नेवर और सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल के साथ मिलकर इस सामग्री से उत्पन्न बढ़ते खतरों पर चर्चा की।

माहूरकर ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने नेटफ्लिक्स, ALTT और X के खिलाफ मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि मुंबई पुलिस ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ पीओसीएसओ अधिनियम का उल्लंघन करने वाली सामग्री के लिए एफआईआर दर्ज की। शिकायत में जीतेन्द्र कपूर, शोभा कपूर, और एकता आर. कपूर का नाम शामिल है क्योंकि वे ALTT के प्रमोटर हैं।" उन्होंने आगे कहा, "स्पष्ट सबूतों के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के कारण मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।"

महुरकर ने इन प्लेटफॉर्म्स की आलोचना करते हुए कहा कि इन पर अश्लील और हानिकारक सामग्री खुलकर उपलब्ध है। X पर हार्डकोर पोर्नोग्राफी, नग्नता, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी यौन गतिविधि और जानवरों के साथ यौन क्रिया के वीडियो तक उपलब्ध हैं। ALTT पर अनाचार और दुर्व्यवहार से जुड़े ग्राफिक दृश्य हैं, जो महिलाओं की छवि को नीचा दिखाते

हैं। नेटफ्लिक्स भी ऐसे पोर्नोग्राफिक दृश्य स्ट्रीम कर रहा है, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। माहूरकर ने कहा, "यह सामग्री न केवल नैतिक मुद्दा है, बल्कि यौन हिंसा को भड़का रही है और समाज के ताने-बाने को नष्ट कर रही है। यह बलात्कार के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण है।"

उन्होंने बताया कि यौन विकृत सामग्री और पोर्नोग्राफी से नाबालिगों द्वारा बलात्कार जैसे घृणित अपराध सामने आ रहे हैं। पिछले तीन महीनों में सात मामले भाइयों द्वारा बहनों के बलात्कार, दो मामले पिता द्वारा पुत्री के बलात्कार, और एक व्यक्ति द्वारा अपनी मां के साथ बलात्कार के दर्ज किए गए हैं, जिनका संबंध पोर्नोग्राफी देखने से है।

फाउंडेशन का कानूनी और नैतिक रुख

फाउंडेशन का तर्क है कि ये प्लेटफॉर्म बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000), महिलाओं के अशोभनीय चित्रण (निषेध) अधिनियम (1986), और भारतीय न्याय संहिता (BNS) का उल्लंघन कर रहे हैं।

वकील विनीत जिंदल ने कहा, "इस तरह की सामग्री के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से बलात्कार, छेड़छाड़ और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने आगे कहा, "हमारे कानून समाज के मूल्यों की रक्षा और महिलाओं व बच्चों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स, ALTT और X जैसे प्लेटफॉर्म इन कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर रहे हैं।"

जन सुनवाई और कानूनी सुधार की मांग

महुरकर ने बताया कि सितंबर 2024 में फाउंडेशन ने एक जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक पीड़ित और उनके परिवार यौन हिंसा की शिकायत लेकर आए। 200 से अधिक महिलाओं ने गवाही दी कि उनकी दुर्दशा का कारण इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध अश्लील सामग्री रही है।

संजीव नेवर ने कहा, "हम देख रहे हैं कि मनोरंजन के नाम पर हमारी सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं। इस तरह की सामग्री न केवल व्यक्तियों बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक है।"

उन्होंने कहा कि बॉलीवुड भी देश में स्थानीय पोर्न उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। फाउंडेशन की रिपोर्ट्स में लिंक और तारीखों के साथ यह दिखाया गया है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म, जिन्हें अब बच्चे भी आसानी से देख सकते हैं, खुलेआम अश्लील सामग्री प्रसारित कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस अनुसंधान यह स्पष्ट करता है कि ऐसी सामग्री मस्तिष्क की कार्यक्षमता को स्थायी रूप से नष्ट कर रही है।

पूरी तरह से प्रतिबंध और सख्त कानूनों की मांग

सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन ने अश्लील सामग्री का उत्पादन और प्रसारण करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। फाउंडेशन ने सरकार से सख्त कानून लाने का अनुरोध किया है, जिसमें 10-20 साल की सजा और कम से कम तीन साल तक जमानत न देने का प्रावधान हो। माहूरकर ने कहा, "इस तरह की सामग्री से होने वाला नुकसान किसी भी विदेशी आक्रमण से अधिक है। अगर हम इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करते, तो हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देंगे।"

विनीत जिंदल ने कहा, "ऐसे कानूनों की आवश्यकता है, जो न केवल उत्पादकों बल्कि वितरकों को भी हतोत्साहित करें। अगर हमें एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज बनाना है, तो शून्य-सहिष्णुता नीति ही एकमात्र उपाय है।"

जन समर्थन और फाउंडेशन की प्रतिबद्धता

सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन को लाखों भारतीयों का समर्थन मिला है, जो अश्लील सामग्री को समाप्त करने के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। माहूरकर ने फाउंडेशन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह जन भागीदारी, कानूनी कार्रवाई, और नीति सुधार के माध्यम से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते रहेंगे।

उन्होंने कहा, "आज की यह घटना रचनाकारों और वितरकों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब समय आ गया है कि ये प्लेटफॉर्म अपने प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं। या तो वे कानून का पालन करें या कानूनी परिणामों का सामना करें।"

नोएडा में सरकारी विभागों के लिए दीवाली के बाद आएगी यीडा की भूखंड योजना, ब्रोशर निकालने की हो रही तैयारी

दीपावली के बाद सरकारी विभागों के लिए यमुना प्राधिकरण की भूखंड योजना आने की उम्मीद है। अभी तक ब्रोशर तैयार न होने के कारण योजना में देरी हो रही है। इस योजना के तहत सरकारी विभागों को उनकी जरूरत के हिसाब से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। कई विभागों को पहले ही सांकेतिक मूल्य पर भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।

ग्रेटर नोएडा। सरकारी विभागों के लिए यमुना प्राधिकरण की भूखंड योजना की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। ब्रोशर तैयार न होने के कारण दीपावली के बाद ही भूखंड योजना आने की उम्मीद है। प्राधिकरण पहली बार सरकारी विभागों के लिए भूखंड योजना निकालने जा रहा है। इसके लिए दस विभागों की ओर से पहले ही प्राधिकरण को प्रस्ताव दिए जा चुके हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, औद्योगिक पार्कों की स्थापना के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने भी यीडा क्षेत्र में अपने कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की पहल शुरू कर दी है। इसके लिए प्राधिकरण से भूखंड आवंटन की मांग की है, प्राधिकरण अभी तक सरकारी विभागों को उनकी जरूरत के हिसाब से भूखंड आवंटन का फैसला करता रहा है।

कई विभागों को सांकेतिक मूल्य पर भूखंडों का आवंटन

कई विभागों को सांकेतिक मूल्य पर भूखंडों का आवंटन हुआ है, लेकिन विभागों की ओर से मांग बढ़ने पर प्राधिकरण ने अब भूखंड योजना के माध्यम से इनके आवंटन का फैसला किया है। इसके लिए विभिन्न सेक्टरों में सरकारी कार्यालयों के लिए नियोजित किए गए भूखंडों को चिह्नित किए गए हैं। बीस भूखंड चिह्नित किए गए हैं।

योजना के लिए तैयार किया जा रहा ब्रोशर

इन भूखंडों की योजना निकालने के लिए ब्रोशर तैयार किया जा रहा है। इसमें भूखंड आवंटन की प्रक्रिया, दर एवं अन्य शर्त, नियमों की जानकारी होगी। दीपावली से पहले भूखंड योजना निकालने का फैसला किया गया था, लेकिन दीपावली नजदीक है और अभी तक ब्रोशर तैयार नहीं हो पाया है।

सरकारी विभागों के लिए भूखंड योजना

ऐसे में दीपावली के बाद ही सरकारी विभागों के लिए भूखंड योजना आने की उम्मीद है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि दीपावली से पहले योजना निकालने का प्रयास हो रहा है। अगर ब्रोशर तैयार नहीं हो पाया तो त्योहार के बाद इस योजना को निकाला जाएगा।

चोला स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन के रूप में होगा विकसित

यमुना प्राधिकरण दिल्ली हावड़ा रूट के चोला स्टेशन को मुख्य रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करेगा। यमुना प्राधिकरण ने रेल मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। चोला से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 16 किमी लंबा एक्सप्रेस-वे बनाकर जोड़ा जाएगा।

इसके दोनों ओर लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के सेक्टर विकसित किए जाएंगे। प्राधिकरण एक्सप्रेस-वे व नए सेक्टरों के लिए नौ गांव की 3690 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसका प्रस्ताव तैयार का जल्द जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। एक्सप्रेस-वे बनने से नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा।

सामने आए यति नरसिंहानंद गिरी, वीडियो जारी कर पुलिस पर लगाया नजरबंदी का आरोप; CM योगी से की ये अपील

यति नरसिंहानंद गिरी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने पुलिस पर उन्हें गैरकानूनी तरीके से नजरबंद रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रयागराज उच्च न्यायालय में पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए अपने बयान के खिलाफ दायर जनहित याचिका का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें रिहा किया जाए ताकि वह अदालत में अपना पक्ष रख सकें।

गाजियाबाद। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में यति नरसिंहानंद ने आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिस ने गैरकानूनी नजरबंदी में रखा हुआ है। वीडियो में यति बोल रहे हैं कि प्रयागराज उच्च न्यायालय में उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में दिए गए बयान के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। यति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें पुलिस की नजरबंदी से निकाला जाए जिससे वह उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकें। यति नरसिंहानंद चार अक्टूबर की रात डासना देवी मंदिर पर उग्र भीड़ के पहुंचने के बाद से लापता हैं। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि पुलिस अधिकारी यति को अपने साथ किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए थे, जबकि पुलिस का कहना है कि यति कहां है इसकी जानकारी नहीं है।

बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप, प्राधिकरण ने भूमाफिया के कब्जे से खाली कराई 50 करोड़ की जमीन

नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर में 50 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। प्राधिकरण की टीम ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वाल और टीन शेड हटाए। कुछ पक्का निर्माण भी तोड़ा गया। यह जमीन प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित है। यहां प्लॉटिंग कर लोगों को सस्ते प्लॉट बेचने का काम हो रहा था।

नोएडा। प्राधिकरण का अवैध निर्माण को भूमाफिया के खिलाफ अभियान जारी है। बृहस्पतिवार को सर्किल-6 की टीम ने सलारपुर में करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यहां बाउंड्रीवाल और टीम शेड लगाकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। कुछ पक्का निर्माण भी कराया गया था, जिसे प्राधिकरण के बुलडोजर ने ध्वस्त किया। जमीन प्राधिकरण की मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित है।

प्राधिकरण वर्क सर्किल छह वरिष्ठ प्रबंधक केबी सिंह ने बताया कि सलारपुर में खसरा नंबर- 595, 596, 597 और 598 करीब पांच हजार वर्गमीटर जमीन है। इस जमीन के चारों ओर बाउंड्री कराकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। यहां प्लॉटिंग कर लोगों को सस्ते प्लॉट बेचने का काम हो रहा था।

प्राधिकरण को जानकारी मिलने पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा आसपास भी कई स्थानों पर अवैध निर्माण हो रहा है। वहां अंतिम नोटिस चस्पा किया गया है। अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है। यदि वे नहीं हटाते तो कानूनी कार्रवाई के साथ निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।

दस माह में दो लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त

प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस जमीन की लागत 1068 करोड़ रुपये आकी गई है। इसके अलावा अभियान निरंतर जारी है। यह जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और परियोजनाएं बनाई जानी है। इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि 118 मामलों में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है।

समाप्त कर दी गई है आवासीय भूखंड योजना

नोएडा में उद्यम संचालित करने के लिए पहले प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक उद्यमी को आरक्षित श्रेणी के आवासीय भूखंड आवंटित किया जाता है लेकिन विगत कुछ वर्षों से प्राधिकरण ने श्रेणी के अंतर्गत आवासीय भूखंड योजना समाप्त कर दी गई है। इस कारण उद्यमी अपना उद्योग चलाने के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों से आना-जाना पड़ता है, जिसमें समय के साथ-साथ धन भी व्यय होता है।

पटरी बाजार बनाकर किया था अतिक्रमण

वर्तमान में औद्योगिक सेक्टरों में सड़कों के दोनों ओर रेहड़ी ठेली, खोमचे वालों ने पटरी बाजार बनाकर अतिक्रमण कर दिया गया है, जो कि निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण उद्यमियों को अपने आवास से इकाई तक पहुंचने तथा इकाई से घर पहुंचने में सड़क पर लगन जाम के कारण अत्यधिक समय लगता है। जाम के कारण ईंधन की खपत भी होती है।

कितनी संपत्ति के मालिक हैं संजीव शर्मा? भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद सीट से बनाया उम्मीदवार

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके पास 59.21 लाख रुपये की चल संपत्ति और 18.65 लाख रुपये की अचल संपत्ति है। संजीव शर्मा की पिछले वित्तीय वर्ष में कमाई 5.24 लाख रुपये है जबकि उनकी पत्नी की कमाई 9.41 लाख रुपये है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा (BJP candidate Sanjeev Sharma) ने कलक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने खुद के ऊपर एक आपराधिक मामला लंबित होना बताया है, वह पुतला फूंकने से संबंधित है।

भाजपा प्रत्याशी के पास 59.21 लाख रुपये की चल संपत्ति और 18.65 लाख रुपये की अचल संपत्ति हैं। उनकी पत्नी रितु शर्मा पेशे से सरकारी अध्यापिका हैं। उनके पास 61.16 लाख रुपये की चल संपत्ति और 1.34 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है।

संजीव के पास नकदी के रूप में 42 हजार रुपये

भाजपा प्रत्याशी के पास स्कूटी है जबकि उनकी पत्नी के पास कार है। संजीव शर्मा की पिछले वित्तीय वर्ष में कमाई 5.24 लाख रुपये है जबकि उनकी पत्नी की कमाई 9.41 लाख रुपये है। संजीव ने खुद के पास नकदी 42 हजार रुपये बताई है जबकि उनकी पत्नी के पास 65 हजार रुपये है।

संजीव शर्मा की प्रॉपर्टी का ब्योरा

भारतीय जनता पार्टी
नाम - संजीव शर्मा
पता - शालीमार गार्डन
चल संपत्ति - 59.21 लाख रुपये
अचल संपत्ति - 18.65 लाख रुपये
आजीविका का साधन - व्यापार
शिक्षा - बीकॉम
आपराधिक मामला - एक
कर्ज - शून्य

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को जानिए

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट (Ghaziabad city assembly seat) पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी के तौर पर संजीव शर्मा (Sanjeev Sharma) को उतारा है। संजीव साल 2007 में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए थे। गाजियाबाद महानगर में संगठन को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही, यही वजह रही कि पार्टी ने अब उनको बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है।

शर्मा को 2019 में भाजपा के महानगर अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। संजीव के महानगर अध्यक्ष बनने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद महानगर के अंतर्गत आने वाली गाजियाबाद शहर, साहिबाबाद और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में तीनों विधायकों ने पहले से ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की।

संजीव ने भाजपा (UP BJP) में शामिल होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पद पर तीन साल तक कार्यरत रहे। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने युवाओं को भाजपा से जोड़ा।

जम्मू-कश्मीर में नई शुरुआत

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

यह पहली बार हुआ कि इतने ज्यादा विधायकों ने कश्मीरी भाषा में शपथ ली। यहां तक कि मुश्किल से कश्मीरी भाषा बोलने वाले उमर अब्दुल्ला ने विधायक पद की शपथ कश्मीरी में ली..

उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की कमान संभाल ली है। 2014 में उन्हें पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने अपदस्थ कर दिया था। वैसे कश्मीर में सैयदों की और देसी मुसलमानों की लड़ाई बहुत पुरानी है। मुफ्ती साहिब के इंतकाल के बाद उनकी बेटी सैयदा महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री बन गई थीं। मुफ्ती परिवार का यह राजयोग भाजपा के समर्थन पर टिका था। वैसे यह भी अपने आप में सातवां आश्चर्य ही था कि जनसंघ/भाजपा शुरू से ही स्वदेशी का ही समर्थन करती रही हैं, लेकिन जब कश्मीर में राजसत्ता देने की बात आई तो फैसला सैयदों के हक में दे दिया। इससे राज्य के गुज्जर, दलित और पसमांदा मुसलमान भाजपा से रुष्ट भी हुए थे। लेकिन अब यह पुरानी बात है। वैसे भी हालात कुछ ऐसे बने कि भाजपा ने अपना सहयोग वापस ले लिया। जाहिर है इससे मुफ्ती परिवार के हाथ की लकीरें भी बदल गईं। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में इतना कुछ बदल गया जिसको समझने समझाने में समाजविज्ञानियों को पसीना आने लगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में हडक़म्प मच गया। अमेरिका ने बहुत ही चालाकी से भारत को इस मुद्दे पर घेरा हुआ था। दुनिया भर को विश्वास दिला रखा था कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। इन गोरे लोगों ने चाल इतनी ख़ूबसूरती से चली थी कि भारत में भी बहुत से लोग विश्वास करने लगे थे कि कश्मीर दोनों देशों में विवाद का कारण है। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 था ही। कश्मीर घाटी में तो इस मृगमरीचिका का शिकार होकर बहुत से कश्मीरी भी आजादी-आजादी चिल्लाते हुए, पाकिस्तान के साथ जाने के सपने देखने लगे। इसलिए सैयदों की इन अरबी चालों और गोरों की नस्ली चालों को सदा के लिए दफनाने के लिए भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को ही हटा दिया। हडक़म्प मचना तय ही था। लेकिन ज्यादा हो-हल्ला तीन डेरों पर ही मचा। पहला डेरा अब्दुल्ला परिवार का था। यह डेरा जम्मू कश्मीर का स्थानीय या लोकल डेरा था।

यह ठीक है कि डेरे के पूर्वज कभी अति उत्साह में अरबी शेख बनने चले थे, शायद कश्मीरियों को डराने के लिए ही। लेकिन वे जल्दी समझ गए कि दूसरों के कपड़े पहन कर देवदार को खजूर समझने से मानसिक तनाव ही बढ़ता है, इसलिए वे जल्दी ही नकली शेख की वर्दी उतार कर अपने देसी लोगों में ही शामिल हो गए। दूसरा डेरा सैयदों का था। वे अभी भी देवदारों पर खजूरें लगने की तरकीबें तलाश रहे थे। तीसरा डेरा उन अलगाववादियों का आकार ले रहा था जिनका नियंत्रण तो एटीएम (अरब-तुर्क-मुगल) मूल के विदेशी मुसलमानों के हाथ में ही था, लेकिन मजहब के नाम पर उन्होंने कुछ देसी कश्मीरी भी अपने डेरे में बिठा रखे थे। जैसे ही अनुच्छेद 370 खत्म हुआ हड़बड़ाहट में ये तीनों डेरे गुपकार के नाम पर एक साथ रोने लगे। लेकिन इतनी बेसुरी आवाजें निकलीं कि उसमें कश्मीर कहीं सुनाई नहीं दे रहा था। देसी डेरे ने तो अरसा पहले ही अरबी शेख बनने का गैर कश्मीरी रास्ता छोड़ दिया था। वह समय की चाल को भी समझ गया था और समय के महत्व को भी। फिर वह जम्मू कश्मीर का देसी डेरा था, राज्य के देसी मन को कैसे न समझता! अरबी डेरे न तो कश्मीर के मन को समझ पाए और न ही समय की चाल को। यही कारण है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में अरबी डेरे उखड़ गए और देसी डेरों ने धमाल मचा दी। जम्मू संभाग में भाजपा ने झंडे गाड दिए और कश्मीर संभाग में अब्दुल्ला परिवार की नैशनल कान्फ्रेंस ने अंगद की तरह पैर जमा दिया। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनना ही था, लेकिन अनुमान इस बात को लेकर लगाया जा रहा था कि विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद भी क्या वे राज्य के भीतर की देसी अभिलाषा को पढ़ते रहेंगे या फिर विदेशी भाषा की चालों में फंस जाएंगे। उमर के मंत्रिमंडल को देख कर लगता है वे भूतकाल से निकल कर भविष्य के रास्ते पर चलने का निर्णय कर चुके हैं। चुनाव से पहले नैशनल कांन्फ्रेंस ने कांग्रेस से समझौता किया हुआ था।

जम्मू संभाग की अधिकांश सीटें राहुल गांधी के हवाले करते हुए उसे उसी का मंत्र भी याद दिला दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन राहुल गांधी संख्या लेकर हाजिर हुए महज छह की। उसमें भी पांच लोग तो उमर अब्दुल्ला के इलाके कश्मीर के ही थे और जीते भी नैशनल कान्फ्रेंस की मदद से ही थे। कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खडग़े दिल्ली में बुढ़ापा नृत्य करते रहे कि जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन जीत गया है, लेकिन उमर ने अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस को शामिल ही नहीं किया। अलबत्ता राहुल गांधी ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर की कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनकी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। कश्मीर से सकीना इट्टू को मंत्री बनाया गया है। कश्मीर से दूसरे मंत्री जावेद अहमद डार मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री समेत कश्मीर संभाग से तीन सदस्य हैं। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। राजौरी जिला में उनकी पार्टी के सुरेन्द्र चौधरी जीते थे। उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह अलग बात है कि चौधरी पीडीपी से शुरू करके, भाजपा से होते हुए नैशनल कान्फ्रेंस तक पहुंचे हैं। पुंछ जिला से नैशनल कान्फ्रेंस के ही जावेद अहमद राणा मंत्री बनाए गए हैं। इस प्रकार पीर पंजाल से दो मंत्री हो गए। लेकिन जम्मू के मैदानी इलाकों का क्या किया जाए? उमर इसे छोड़ सकते थे। आखिर उसकी पार्टी को वहां से मिला ही क्या था? लेकिन उन्होंने छम्ब से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके अपनी ओर से संतुलन बनाए रखने का हरसंभव प्रयास किया है। शपथ ग्रहण करने से पूर्व ही उन्होंने अपनी ओर से धुंध साफ करने का प्रयास करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि वे जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में अनुच्छेद 370 के पुनः जीवित हो उठने का कोई मौका नहीं है। इसलिए वे अपनी ओर से राज्य के लोगों को अन्य नेताओं की तरह झूठे आश्वासन नहीं दे सकते और न हीं देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां तक राजनीतिक दल की हैसियत का सवाल है, नैशनल कान्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। इसलिए अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे ही। लेकिन जहां तक सरकारों का सवाल है, राज्य सरकार केन्द्र सरकार से तालमेल बना कर ही चलेगी।

इससे जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला केवल यथार्थ के धरातल पर ही नहीं खड़े हैं, बल्कि भारत की भीतरी एकात्मता को पहचान रहे हैं। राहुल गांधी के 'जलेबी स्तर' और उमर अब्दुल्ला के 'चिंतन स्तर' का यही अंतर राज्य में भविष्य की राह बनाएगा। यह भी शायद पहली बार ही हुआ है कि राज्य मंत्रिमंडल में एटीएम गायब है। इसमें देसी कश्मीरी तो हैं, लेकिन सैयद कोई नहीं है। अन्यथा अभी तक संख्या में महज लाख से भी कम होने के बावजूद कब्जा सैयदों व मुगलों का ही होता था। लेकिन एक कमी अभी भी खलती है। इस्लाम पंथ के लोग तो मंत्रिमंडल में हैं, एक शिया पंथ का प्रतिनिधि भी शामिल कर लिया जाता तो पूरा संतुलन बैठ जाता। कश्मीर से शेख और सैयद सत्ता से छिटक रहे हैं, यह अनुमान लगा कर अब्दुल्ला परिवार ने तो शेख वाला अरबी टोप उतार दिया है। सैयद भी देसी सफों में घुस गए। यह पहली बार हुआ कि इतने ज्यादा विधायकों ने कश्मीरी भाषा में शपथ ली। यहां तक कि मुश्किल से कश्मीरी भाषा बोलने वाले उमर अब्दुल्ला ने विधायक पद की शपथ कश्मीरी में ली। विधानसभा के कुछ सदस्यों ने तो संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की। जम्मू वालों ने तो डोगरी में शपथ लेनी ही थी लेकिन एक सदस्य ने शीना भाषा में प्रतिज्ञा की। पहली बार लगा कि यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा है और भाषा में ही बोलती है।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV

Drive the Future

युमा एनर्जी ने नोएडा में बैटरी स्वैपिंग सेवा शुरू की, पूरे उत्तर प्रदेश में करेगी विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

युमा एनर्जी ने नोएडा में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। यहां से लोगों को महज एक मिनट में चार्ज बैटरी मिल जाएगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोग अब अलग-अलग जगहों पर रुककर चार्जिंग का इंतजार करने की बजाय डिस्चार्ज बैटरी को नोएडा में जमा करा सकेंगे और वहां से एक मिनट में पूरी तरह चार्ज बैटरी प्राप्त कर सकेंगे।

स्वैपिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने की योजना के साथ कंपनी का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विस्तार करना है। इसके लिए कंपनी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में अपने केंद्र स्थापित करने की तैयारी में है। कंपनी के इस विस्तार के साथ ही युमा एनर्जी उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से 500 प्रत्यक्ष रोजगार और एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

युमा एनर्जी इस समय देशभर में हर महीने करीब 15 लाख बैटरियां बदलती है। यानी डिस्चार्ज बैटरियां लेकर लोगों को चार्ज बैटरियां मुहैया करा रही है। कंपनी अपनी बैटरी स्वैपिंग सेवाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए फास्ट चार्जिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिससे बैटरी स्वैप करने का समय घटकर महज एक मिनट रह जाएगा। ऐसे में लोगों को सेंटर पहुंचकर अपने वाहन की बैटरी बदलने में महज एक मिनट लगेगा। इससे कमर्शियल ईवी को काफी फायदा होगा।

युमा एनर्जी के प्रबंध निदेशक मुथु सुब्रमण्यन ने कहा कि ई-मोबिलिटी में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। खासकर थ्री-व्हीलर सेगमेंट में राज्य ने काफी तेजी से प्रगति की है। इसके लिए राज्य द्वारा ई-मोबिलिटी के लिए अपनाई गई अनुकूल नीति काफी फायदेमंद साबित हुई है। नोएडा में कंपनी की शुरुआत से शहर के लोगों को सुविधा मिलेगी जो तेजी से ईवी अपना रहे हैं इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथमेश कुमार ने युमा एनर्जी की पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। कंपनियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में इन्वेस्ट यूपी की भूमिका अहम रही है।

ई-रिक्शा की जनहित याचिका पर काउंटर दाखिल

परिवहन विशेष न्यूज

ई-रिक्शा से जुड़ी जनहित याचिका पर बुधवार, 23 अक्टूबर को प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना काउंटर दाखिल किया। कोर्ट को बताया गया कि ई-रिक्शा को लेकर कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ई-रिक्शा से जुड़ी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरठ के किशन कंपाउंड निवासी मनोज कुमार चौधरी आरटीआई/सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ई-रिक्शा की बढ़ती दिक्कतों के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

मनोज ने आरोप लगाया था कि हजारों ई-रिक्शा तेज रफ्तार से चल रहे हैं और शहर की यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इनको लेकर न तो प्रशासन और न ही आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस ने कोई प्लानिंग की है। जनहित याचिका स्वीकार होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोर्ट से काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। 20 सितंबर का समय दिया गया लेकिन कोर्ट सत्र में न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 23 अक्टूबर की तिथि तय की। प्रशासन ने अपने जवाब में ई-रिक्शा को लेकर 20 जून को जिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला दिया है। 12 सितंबर को एसपी ट्रैफिक ने रूट निर्धारण के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताया। इतना ही नहीं रूट निर्धारण के लिए तैयार की गई गाइड लाइन का भी पूरा ब्योरा दिया है।

आरटीआई कार्यकर्ता मनोज चौधरी का कहना है कि प्रशासन ने काउंटर दाखिल किया है। इसमें कई तरह की खामियां नजर आ रही हैं। 25 अक्टूबर से कोर्ट की छुट्टी है, इसलिए दिवाली की छुट्टी खत्म होने के बाद वह रिज्वाइंडर दाखिल करेंगे।

ई-रिक्शा चालकों को भी लेना होगा प्रशिक्षण, तभी होगा आरटीओ में रजिस्ट्रेशन

परिवहन विशेष न्यूज

मेरठ में अब नई ई-रिक्शा का संभागीय परिवहन में रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब चालक के पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा। इसके लिए ई-रिक्शा चालक को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दस दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। हालांकि इस नई व्यवस्था का विरोध भी शुरू हो गया है। ई-रिक्शा चालकों ने इस नई व्यवस्था के विरोध में 25 अक्तूबर को हड़ताल की चेतावनी दी है।

शहर की सड़कों पर ई-रिक्शा की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर का कोई चौराहा ऐसा नहीं जहां पर ई-रिक्शा के बेतरतीब खड़े होने के कारण जाम न लगता हो। यातायात नियमों की जानकारी का ई-रिक्शा चालकों में अभाव है। इस समस्या का समाधान करने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। हालांकि यह नया आदेश अब उन्हीं ई-रिक्शा चालकों पर लागू होगा जो अब नया ई-रिक्शा खरीदेंगे और आरटीओ विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचेंगे। इस संबंध में संभागीय परिवहन विभाग के आरआई राहुल शर्मा का कहना है कि विभाग की तरफ से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ही ई-रिक्शा चालक प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रमाण पत्र लेंगे। शीघ्र ही मेरठ के एक स्कूल को मान्यता दी जाने की तैयारी है। ई-रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण में यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इससे ई-रिक्शा चालक भी सुरक्षित रहेंगे और शहर को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। ई-रिक्शा चालकों के हित में यह कदम उठाया जा रहा है। ई-रिक्शा चालकों का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले सप्ताह कार्यालय में भी आया था।

ईवी जस्ट ट्रांजिशन: सतत गतिशीलता की ओर एक संतुलित बदलाव : राखी शर्मा

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर वैश्विक परिवर्तन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे-जैसे देश और उद्योग ईवी को अपना रहे हैं, रन्यायसंगत परिवर्तनर की अवधारणा को प्रमुखता मिली है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलाव न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक व्यवधानों के साथ उचित और न्यायसंगत हो। भारत में, यह परिवर्तन विशेष रूप से जटिल है, क्योंकि यह देश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। जबकि ईवी क्षेत्र आर्थिक उन्नति के लिए कई अवसर प्रदान करता है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करता है। पारंपरिक ऑटोमोटिव उद्योगों में श्रमिकों के लिए।

जस्ट ट्रांज़िशन को समझना

न्यायसंगत परिवर्तन से तात्पर्य जीवाश्म-ईंधन-आधारित उद्योगों से हरित विकल्पों में बदलाव को इस तरह से प्रबंधित करने के जानबूझकर किए गए प्रयास से है जो श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है। ईवी क्षेत्र के संदर्भ में, इसका मतलब रोजगार के नए अवसर पैदा करना, विस्थापित श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईवी विनिर्माण, बैटरी उत्पादन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास जैसे उभरते उद्योगों में कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

भारत का ईवी परिवर्तन: वर्तमान परिदृश्य

भारत अपने ईवी परिवर्तन में तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (एफएएमई), ईएमपी, एस और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) कार्यक्रम को तेजी से अपनाने और विनिर्माण जैसी नीतियों में परिलक्षित होते हैं। बैटरियां. 2030 तक, भारत का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण के साथ-साथ 30% निजी कारों, 70% वाणिज्यिक वाहनों और 80% दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है।

नीति आयोग के अनुसार, भारत को 2030 तक सड़क पर लगभग 90 मिलियन ईवी होने की उम्मीद है, जो जीवाश्म ईंधन पर इसकी निर्भरता को काफी कम कर देगा और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान देगा। 2023 में, इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान होगा। भारत में कुल वाहन बिक्री का 6.75%, जो साल-दर-साल 40% की वृद्धि दर्शाता है।

ईवी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विनिर्माण, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बैटरी उत्पादन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा हो रहे हैं। जैसे-जैसे देश 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, रोजगार सृजन की संभावना बहुत अधिक है। यहां डेटा और उद्योग अनुमानों द्वारा समर्थित रोजगार के अवसरों का अवलोकन दिया गया है।

1. विनिर्माण और असेंबली नौकरियां:

* **वाहन उत्पादन:** उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारत का ईवी विनिर्माण उद्योग 2030 तक 5 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने के लिए तैयार है। इसमें वाहन संयोजन, घटक निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में भूमिकाएँ शामिल हैं।
* **बैटरी विनिर्माण:** उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए भारत सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से 2030 तक 50 गीगावॉट वार्षिक बैटरी उत्पादन क्षमता उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप अकेले बैटरी विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 50,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी।

2. बैटरी रीसाइक्लिंग:

ईवी अपनाने में वृद्धि के साथ, बैटरी रीसाइक्लिंग सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। 2030 तक, भारत के बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग में 50,000 नई नौकरियाँ पैदा होने का अनुमान है, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरी प्रसंस्करण, सामग्री पुनर्प्राप्ति और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में।

3. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट:

बढ़ते ईवी बाजार को समर्थन देने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार आवश्यक है। देश को सालाना 400,000 से अधिक चार्जर स्थापित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 2030 तक नौ प्रमुख शहरों में 46,397 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) के लक्ष्य की पहचान की है। यह विस्तार ईवी चार्जिंग पॉइंट की स्थापना, रखरखाव और संचालन में नौकरियां पैदा करेगा। 2030 तक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले 100,000 से अधिक श्रमिकों को सीधे रोजगार दे सकता है।

उद्योग रिपोर्टों के अनुसार, 43 निजी चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर (सीपीओ) और 26 सार्वजनिक सीपीओ फरवरी 2024 तक लगभग 12,146 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे, जिससे इन सुविधाओं के संचालन और प्रबंधन में रोजगार पैदा हुआ।

4. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी):

भारत के ईवी उद्योग में अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि देश स्वदेशी नवाचार में निवेश कर रहा है। बैटरी प्रौद्योगिकी विकास, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन डिजाइन और स्वायत्त ड्राइविंग प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों से हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), PM ई-ड्राइव और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से R&D में सरकार का निवेश इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को और बढ़ाता है।

5. नीति और बाजार विश्लेषण:

जैसे-जैसे भारत ईवी अपनाने के लिए महत्वाकांक्षी नीतियों को लागू कर रहा है, विकसित हो रहे नियामक माहौल को नेविगेट करने में मदद के लिए नीति शोधकर्ताओं, डेटा विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ रही है। नीति आयोग ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गहन बाजार विश्लेषण और नीति मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।

चुनौतियाँ: पारंपरिक क्षेत्रों में विस्थापन

जबकि ईवी क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजन का वादा करता है, यह पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन उद्योग और तेल शोधन और ईंधन वितरण जैसे संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों को भी खतरे में डालता है। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, और ईवी में बदलाव से इस श्रम बाजार में काफी व्यवधान आने की उम्मीद है।

x ऑटोमोटिव विनिर्माण:

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों की तुलना में कम चलने वाले हिस्से होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें इंजन, ट्रांसमिशन या निकास प्रणाली जैसे जटिल यांत्रिक घटकों की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के अनुसार, इस बदलाव के परिणामस्वरूप नौकरी छूट सकती है, खासकर ऑटो-कंपोनेंट विनिर्माण क्षेत्र में। छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई), जो बड़े पैमाने पर आईसीई वाहनों के लिए भागों के उत्पादन पर निर्भर हैं, इस संक्रमण से विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

x जीवाश्म ईंधन उद्योग:

जैसे-जैसे भारत पेट्रोलियम-आधारित परिवहन से विद्युत गतिशीलता की ओर बढ़ रहा है, ईंधन निष्कर्षण, रिफाइनिंग और वितरण जैसे क्षेत्रों में संभावित नौकरी के नुकसान के बारे में चिंता बढ़ रही है। असम और गुजरात जैसे राज्य, जो प्रमुख तेल रिफाइनरियों का घर हैं और इन उद्योगों में रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अकेले गुजरात भारत की कुल कच्चे तेल शोधन क्षमता में 20% से अधिक का योगदान देता है और अपनी रिफाइनरियों और संबंधित क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसी तरह, असम, जो भारत के तटवर्ती कच्चे तेल की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करता है, स्थानीय रोजगार के लिए इन उद्योगों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। विद्युत गतिशीलता में बदलाव से मूल्य श्रृंखला में श्रमिकों को निष्कर्षण और शोधन से लेकर परिवहन और खुदरा वितरण तक विस्थापित किया जा सकता है।

x वाहन रखरखाव:

आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को काफी कम बार और सरल रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिससे मरम्मत और सेवा उद्योगों में रोजगार में संभावित कमी आती है। ईवी में आईसीई वाहनों की तुलना में लगभग 60% कम चलने वाले हिस्से होते हैं, जिससे तेल परिवर्तन, स्पार्क प्लग प्रतिस्थापन और निकास प्रणाली की मरम्मत जैसी नियमित सेवाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस कम हुई जटिलता से समग्र ऑटोमोटिव मरम्मत बाजार में 30-40% की कमी आने का अनुमान है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, यह अनुमान है कि ईवी अपनाने में वृद्धि के कारण 2040 तक कार रखरखाव से संबंधित लगभग 80,000 नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। स्थिति भारत में भी ऐसी ही है, जहां पारंपरिक रूप से आईसीई वाहनों में विशेषज्ञता रखने वाले मैकेनिकों को दोबारा प्रशिक्षित न किए जाने पर नौकरी से विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है।

कार्यबल को पुनः कुशल बनाना

भारत के ईवी क्षेत्र में उचित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, पुनः कौशल कार्यक्रमों में निवेश करना और आईसीई से ईवी प्रौद्योगिकियों में बदलाव से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। संक्रमण को समान रूप से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग शामिल हो।

x पुनः कौशल विकास और उन्नयन:

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में कार्यबल को कुशल और उन्नत बनाने के उद्देश्य से कई पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये प्रयास ईवी उद्योग के तेजी से विकास का समर्थन करने और टिकाऊ गतिशीलता के लिए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ईवी विनिर्माण, बैटरी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और वाहन रखरखाव जैसे क्षेत्रों में विशेष कौशल विकसित करने पर केंद्रित हैं।

x ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी)

एएसडीसी भारत की अग्रणी संस्था है जो ऑटोमोटिव क्षेत्र में कौशल विकास के लिए समर्पित है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक, बैटरी रखरखाव तकनीशियन, ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर और इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन तकनीशियन जैसी ईवी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिसका लक्ष्य 2026 तक 1,00,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

x राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

एनएसडीसी ने ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) के सहयोग से ईवी विनिर्माण, बैटरी प्रौद्योगिकी और ईवी रखरखाव में कौशल विकसित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, एनएसडीसी ने अपने कार्यक्रमों को टाटा, एथर एनर्जी जैसे प्रमुख ईवी निर्माताओं की जरूरतों के साथ जोड़ा है। और ओला इलेक्ट्रिक। एनएसडीसी का लक्ष्य 2025 तक ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में 500,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है।

x प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

पीएमकेवीवाई 4.0 योजना के तहत, ईवी प्रौद्योगिकी सहित हरित अर्थव्यवस्था के लिए कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। वे ईवी विनिर्माण और असेंबली, बैटरी प्रबंधन प्रणाली और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 2023 तक, 150,000 से अधिक श्रमिकों को पीएमकेवीवाई के तहत ईवी-संबंधित कौशल में प्रशिक्षित किया गया है, 2025 तक इसे 250,000 श्रमिकों तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

x कौशल भारत मिशन

व्यापक कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में, सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में श्रमिकों के कौशल और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्किल इंडिया पहल के माध्यम से, सरकार ईवीएस सहित हरित अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में 2030 तक 2 मिलियन श्रमिकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रख रही है।

भारत में कई राज्य उभरते उद्योगों में कुशल श्रम की बढ़ती मांग के जवाब में अपने कार्यबल को कुशल बनाने के लिए सक्रिय रूप से पहल कर रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय आर्थिक विकास को गति देने और भविष्य के लिए तैयार उद्योगों में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ये पहल महत्वपूर्ण हैं। कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके, ये राज्य न केवल नई नौकरी के अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि भारत के नेट-शून्य संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी को भी संबोधित कर रहे हैं। ये प्रयास स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित हैं जो जमीनी स्तर पर नवाचार और स्थिरता का समर्थन करता है।

सहयोग:

ईवी कंपनियों के साथ साझेदारी छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप सुनिश्चित करती है, जिससे नौकरी की तैयारी बढ़ती है। भारत सरकार को, ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ साझेदारी में, आईसीई वाहन निर्माण और रखरखाव में श्रमिकों के लिए कौशल भारत मिशन और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसे ईवी क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए। विशेष रूप से बैटरी प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग:

इंजीनियरिंग कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को ईवी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और स्मार्ट गतिशीलता समाधानों पर पाठ्यक्रम शामिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन करना चाहिए। उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी यह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप हों।

सरकारी नीतियां न्यायोचित परिवर्तन का समर्थन करती हैं

भारत सरकार ने ईवी क्षेत्र में उचित बदलाव की सुविधा के लिए कई नीतियां पेश की हैं, जिसका लक्ष्य सामाजिक समानता के साथ रोजगार सृजन को संतुलित करना है।

1. FAME योजनाएँ: सरकार FAME, EMPS और PM e-DRIVE जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्योग को नियमित रूप से समर्थन दे रही है। हालिया योजना पीएम ई-ड्राइव सरकार। ने ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और परीक्षण एजेंसियों जैसे नए कार्यक्षेत्र पेश किए हैं। ईवी अपनाने को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक बसों, दोपहिया वाहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की मांग पैदा करने के लिए आवंटित बजट 10900 करोड़ रुपये है। इससे ईवी विनिर्माण और सेवाओं में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।

2. ईवी और एसीसी बैटरियों के लिए पीएलआई योजना: ईवी और एसीसी बैटरियों के लिए पीएलआई योजना से ईवी घटकों और बैटरियों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके, आयात पर निर्भरता कम करके 50,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

3. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति का मसौदा: यह नीति कौशल विकास, अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाने और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष

भारत का इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। ईवी क्षेत्र लाखों नई नौकरियाँ पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पारंपरिक उद्योगों में महत्वपूर्ण व्यवधान भी आएगा। एक उचित परिवर्तन के लिए पुनः कौशल और बुनियादी ढांचे के विकास में सावधानीपूर्वक योजना और निवेश की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव में कोई भी पीछे न रह जाए। सही नीतियों और साझेदारियों के साथ, भारत इस परिवर्तन को सफलतापूर्वक पार कर सकता है, और अपने कार्यबल और अर्थव्यवस्था के लिए अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण कर सकता है।

नोबेल पुरस्कारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव चमका

विजय गर्ग

भौतिकी पुरस्कार विजेताओं, विशेष रूप से हिंटन ने मशीन लर्निंग नामक शक्तिशाली क्षेत्र की नींव रखी। यह एआई का एक उपसमूह है जो विशिष्ट कम्प्यूटेशनल कार्यों को करने के लिए एल्गोरिदम, नियमों के सेट से संबंधित है। होपफ़ील्ड का कार्य आज विशेष रूप से उपयोग में नहीं है, लेकिन बैकप्रॉपैगेशन एल्गोरिदम (हिंटन द्वारा सह-आविष्कार) का कई अलग-अलग विज्ञानों और प्रौद्योगिकियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।

नोबेल क्रिस्टियानिनी, बाथ विश्वविद्यालय भौतिकी और रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कारों ने हमें विज्ञान के भविष्य की एक झलक दी है। दोनों पुरस्कारों से सम्मानित खोजों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केंद्रीय थी। आपको आश्चर्य होगा कि पुरस्कारों की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल इस सब के बारे में क्या सोचते होंगे। हमें यकीन है कि एआई उपकरणों का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को कई और नोबेल पदक दिए जाएंगे। जैसा कि ऐसा होता है, हम नोबेल समिति द्वारा सम्मानित वैज्ञानिक तरीकों को ₹भौतिकी₹, ₹रसायन विज्ञान₹ और ₹शरीर विज्ञान या चिकित्सा₹ जैसी सीधी श्रेणियों से हटकर पा सकते हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि प्राप्तकर्ताओं की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि इन श्रेणियों के साथ कमजोर संबंध बनाए रखती है। इस वर्ष का भौतिकी पुरस्कार प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अमेरिकी जॉन हॉपफील्ड और टोरंटो विश्वविद्यालय से ब्रिटिश मूल के जेफ्री हिंटन को प्रदान किया गया। जबकि होपफील्ड एक भौतिक विज्ञानी हैं, हिंटन ने एआई की ओर बढ़ने से पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। रसायन विज्ञान पुरस्कार वाशिंगटन विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट डेविड बेकर और कंप्यूटर वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर के बीच साझा किया गया था, जो दोनों यूके में गुगल डीपमाड में हैं। भौतिकी और रसायन विज्ञान श्रेणियों में सम्मानित एआई-आधारित प्रगति के बीच घनिष्ठ संबंध है। हिंटन ने प्रोटीन के आकार की भविष्यवाणी करने में सफलता हासिल करने के लिए डीपमाइंड द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद की। भौतिकी पुरस्कार विजेताओं, विशेष रूप से हिंटन ने मशीन लर्निंग नामक शक्तिशाली क्षेत्र की नींव रखी। यह एआई का एक उपसमूह है जो विशिष्ट कम्प्यूटेशनल कार्यों को करने के लिए एल्गोरिदम, नियमों के सेट से संबंधित है। होपफ़ील्ड का कार्य आज विशेष रूप से उपयोग में नहीं है, लेकिन बैकप्रॉपैगेशन एल्गोरिदम (हिंटन द्वारा सह-आविष्कार) का कई अलग-अलग विज्ञानों और प्रौद्योगिकियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। यह तंत्रिका नेटवर्क से संबंधित है, कंप्यूटिंग का एक मॉडल जो डेटा को संसाधित करने के लिए मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य की नकल करता है। बैकप्रॉपैगेशन वैज्ञानिकों को विशाल तंत्रिका नेटवर्क को ₹प्रशिक्षित₹ करने की अनुमति देता है। हालाँकि नोबेल समिति ने इस प्रभावशाली एल्गोरिदम को भौतिकी से जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह कहना उचित होगा कि यह लिंक प्रत्यक्ष नहीं है। वायरस प्रोटीन को अब वायरस का मुकाबला करने के लिए तुरंत डिज़ाइन किया जा सकता है। रेडॉक्सिस्ट स्टूडियो / शटरस्टॉक मशीन-लर्निंग सिस्टम को प्रशिक्षित करने में इसे अक्सर इंटरनेट से बड़ी मात्रा में डेटा को उजागर करना शामिल होता है। हिंटन की प्रगति ने अंततः जीपीटी (चैटजीपीटी के पीछे की तकनीक) और गूगल डीपमाइंड द्वारा विकसित एआई एल्गोरिदम अल्फागो और अल्फाफोल्ड जैसे सिस्टम के प्रशिक्षण को सक्षम किया। इसलिए, बैकप्रोपेगेशन का प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। डीपमाइंड के अल्फाफोल्ड 2 ने 50 साल पुरानी समस्या का समाधान किया: उनके आणविक निर्माण ब्लॉकों, अमीनो एसिड से प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करना। 1994 से हर दो साल में, वैज्ञानिक अपने अमीनो एसिड के अनुक्रम से प्रोटीन संरचनाओं और आकृतियों की भविष्यवाणी करने के सर्वोत्तम तरीके खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। प्रतियोगिता को क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कहा जाता है। पिछले कुछ प्रतियोगिताओं के लिए, सीऐएसपी विजेताओं ने डीपमाइंड के अल्फाफोल्ड के कुछ संस्करण का उपयोग किया है। इसलिए, हिंटन के बैकप्रोपेगेशन से गुगल डीपमाइंड के अल्फाफोल्ड 2 की सफलता तक एक सीधी रेखा खींची जानी है। डेविड बेकर ने नए प्रकार के प्रोटीन के निर्माण की कठिन उपलब्धि हासिल करने के लिए रोसेटा नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया। बेकर और डीपमाइंड दोनों के दृष्टिकोण भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए भारी संभावनाएं रखते हैं। श्रेय देना हमेशा से रहा हैनोबेल पुरस्कारों का विवादास्पद पहलू. अधिकतम तीन शोधकर्ता एक नोबेल साझा कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में बड़ी प्रगति सहयोगात्मक है। वैज्ञानिक पत्रों में 10, 20, 30 लेखक या अधिक हो सकते हैं। नोबेल समिति द्वारा सम्मानित खोजों में एक से अधिक टीमें योगदान दे सकती हैं। इस वर्ष हम बैकप्रॉपैगेशन एल्गोरिदम पर अनुसंधान के श्रेय के बारे में और चर्चा कर सकते हैं, जिसका दावा विभिन्न शोधकर्ताओं ने किया है, साथ ही भौतिकी जैसे क्षेत्र में किसी खोज के सामान्य श्रेय के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। अब हमारे पास एट्रिब्यूशन समस्या का एक नया आयाम है। यह लगातार अस्पष्ट होता जा रहा है कि क्या हम हमेशा मानव वैज्ञानिकों और उनके कृत्रिम सहयोगियों के योगदान के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे - एआई उपकरण जो पहले से ही हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। भविष्य में, क्या हम मशीनों को वैज्ञानिकों की जगह लेते हुए देख सकते हैं, जिसमें इंसानों को सहायक भूमिका सौंपी जाएगी? यदि ऐसा है, तो शायद एआई उपकरण को मुख्य नोबेल पुरस्कार मिलेगा, जिसमें मनुष्यों को अपनी श्रेणी की आवश्यकता होगी।

संपादक की कलम से

मोदी-जिनपिंग संवाद के मायने

पांच साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। यह एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय प्रयास माना जा सकता है। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए। अपने-अपने राष्ट्रीय ध्वजों की पृष्ठभूमि में मुलाकात हुई। कुछ मुस्कराए भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की जो शैली होती है, वह गायब रही। दोनों नेता आलिंगनबद्ध नहीं हुए। मुलाकात में गर्मजोशी और अंतरंगता महसूस नहीं हुई। इस द्विपक्षीय संवाद को अंतिम और निर्णायक भी नहीं माना जा सकता। एक तानाशाह किस्म के देश और एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ऐसी मुलाकात और बातचीत, बेशक, एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके जरिए आगे का रास्ता तय किया जा सकता है। यह दो समान शक्तियों के दरमियान समान स्तर का संवाद भी नहीं था, क्योंकि चीन भारत से करीब 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। सामरिक स्तर पर भी चीन एक 'वैश्विक महाशक्ति' है। फिर भी 5 साल के गतिरोध के बाद चीन भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत को सहमत हुआ, इसे प्रत्येक लिहाज से कमतर नहीं आंकना चाहिए। चीन भारत को प्रतिस्पद्र्धी नहीं, सहयोगी मानता है, यह चीन की नई सोच है। दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त करने और सेनाओं के पीछे हटने के समझौते का स्वागत किया है। दोनों नेता मानते हैं कि उनकी सीमाओं पर शांति और स्थिरता रहनी चाहिए। सीमा विवाद निपटाने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन से विदेश मंत्री वांग यी जल्द ही औपचारिक बैठकें शुरू करेंगे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत को एक-दूसरे के प्रति अच्छी धारणा रखनी चाहिए। पड़ोसी होने के नाते सद्भाव से रहने के लिए सही रास्ता खोजने पर काम करना जरूरी है।

दोनों का मानना है कि भारत-चीन के संबंध उनके देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अहम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान और परस्पर संवेदनशीलता के आधार पर ही दोनों देशों के संबंध तय होने चाहिए। लब्बोलुआब यह रहा कि दोनों देश शांति, स्थिरता, सद्भाव, सौहार्द के पक्षधर हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा संभव और व्यावहारिक होगा? अधिकतर राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ बार-बार यह कह रहे हैं कि चीन की फितरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए और भारतीय सैनिकों को हरदम सचेत रहना चाहिए। दरअसल भारत 1947 और चीन 1949 में स्वतंत्र हुए। उस दौर में दोनों ही देश समान स्थितियों में थे। 1960, '65, '70, '80 और 1987 के कालखंडों तक भारत-चीन की अर्थव्यवस्था में कोई खास अंतर नहीं था। हालांकि भारत 23.2 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ चीन की 22.7 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था से आगे था। 1990 के दशक में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला और आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ। वहीं से चीन ने हमें पीछे करना शुरू किया। चीन ने कृषि का निजीकरण किया। उसे वामपंथी शासन और कायदे-कानूनों से मुक्त रखा। चीन ने गांव-गांव में औद्योगिक जोन बनाए, नतीजतन ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन नहीं हुआ।

सोशल मीडिया का भाषा पर प्रभाव

विजय गर्ग

सोशल मीडिया कई मायनों में व्यक्तियों के जीवन जीने के तरीके को बदल रहा है, खासकर संचार क्षेत्र, ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं में। इसका अर्थ यह भी है कि मानव जीवन की एक आवश्यकता प्राप्त हो जायेगी; अन्य प्राणियों के साथ संवाद और बातचीत करना। इसलिए, वैश्वीकरण के युग में, दुनिया भर में बहुत से लोग सोशल मीडिया का उपयोग अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में करते हैं, लेकिन यह उस भाषा को बदलने को प्रभावित करता है जिससे हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं। मेरी राय में, सोशल मीडिया का भाषा पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब लोगों को एक-दूसरे के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है तो सोशल मीडिया के भाषा बदलने के कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं, जैसे आसान संचार। इसलिए, सोशल मीडिया अक्सर मददगार हो सकता है, और भाषा को सकारात्मक मूल्य दे सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम टूल के सोशल मीडिया में वार्तालाप का उपयोग करते हैं, तो हमने अच्छी तरह से समझने के लिए भाषा शब्दकोश में कई नए शब्द जोड़े हैं और स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बेहतर त्वरित प्रतिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, बहुत से लोग इस प्रकार के संचार का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ संवाद करने का संक्षिप्त तरीका बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि संक्षिप्ताक्षर, इमोटिकॉन, चित्र, प्रतीक, विशिष्ट शब्दावली और अर्थ। इसके अलावा, संचार को आसानी से करने के लिए कई लोग गलतियों को सुधारने के साथ सीखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक उपकरण के रूप में करते हैं, जिससे ऑनलाइन बातचीत में मदद मिलती है जब आप जिस श्रोता से बात कर रहे होते हैं वह गलत वर्तनी को सही करता है, या आप उसे गलत तरीके से लिखते हैं। यह विधि गलतियों से तेजी से सीखने और उन्हें सुधारने में मदद करेगी। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत हैं कि वे भाषा के चित्रात्मक उपयोग के कारण दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इसे नहीं समझते हैं, यह पीढ़ी के अंतर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, भाषा पर सोशल मीडिया के प्रभाव से जिस तरह की भाषा आ रही है, उसे 21वीं सदी की पीढ़ी ही

इस्तेमाल और समझ सकती है और न ही अन्य पीढ़ियां ऐसा कर सकती हैं। नतीजतन, बदलती भाषा पर सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव को भाषा को और अधिक आसान बनाने और हमेशा विकास में योगदान देने के लिए महत्व दिया जा सकता है। फिर भी, कई नकारात्मक प्रभाव हैं कि जब लोगों को एक-दूसरे के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है तो सोशल मीडिया भाषा बदल देता है जैसे कि लोग ज्यादातर समय विकृत शब्दों और मातृभाषा से विचलन करते हैं। इसके अलावा, जब वक्ता कठबोली भाषा और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं तो गलतियाँ करते हैं और वे कुछ शब्दों को छोटा कर देते हैं। इसके अलावा, कई लोग गलत व्याकरण और अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं, विचारों को शब्दों की तुलना में चित्रों में प्रदर्शित करते हैं या किसी संक्षिप्तीकरण का उपयोग करते हैं तो शब्दों को विकृत कर देते हैं। परिणामस्वरूप, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें लोग हर काम जल्दी-जल्दी करते हैं। भाषा का सही ढंग से सही संरचना के साथ प्रयोग करने का समय इस सदी में किसी के पास नहीं है। फिर, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें लोग हर काम जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। किसी के पास भाषा को पूरी सोच और व्याकरण के साथ इस्तेमाल करने का समय नहीं है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें लोग चीजों को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक उपयोगकर्ता #हैशटैग जैसे शब्दों को छोटा करने के लिए उपयोग करते हैं। पूर्ण विचार, अर्थ नहीं होते और सभी लोग शब्द को नहीं समझते। परिणामस्वरूप, भाषा अपनी जड़ें खो देगी, बुजुर्ग लोग इस प्रकार के संचार को नहीं समझ सकते हैं और उपयोगकर्ता इस प्रकार की भाषा के सही उपयोग में आलसी हो जाते हैं। सोशल मीडिया का भाषा पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह सकारात्मक प्रभाव से कहीं अधिक है। इसका मतलब यह है कि भाषाव्याकरणिक रूप से बदलना हो जाता है, बोलना तेजी से बदलता है और सोशल मीडिया डोमेन कोई वास्तविक दुनिया नहीं है। उदाहरण के लिए, जब सोशल मीडिया पर किसी शब्द का इस्तेमाल ट्रेंड बन जाता है तो सभी उपयोगकर्ता उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भाषा को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सभी ट्रेंडी शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जब सोशल मीडिया पर नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो मौजूदा भाषा का इस्तेमाल कम होता है। परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया द्वारा भाषा बदलने के नकारात्मक प्रभाव से संचार में बाधाएं पैदा होती हैं, शब्दावली कमजोर हो जाती है और प्रतीकों के माध्यम से संचार में लौटने की संभावना बढ़ जाती है।

निष्कर्ष में, सोशल मीडिया के भाषा पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक से अधिक हैं क्योंकि भाषा की कुछ संरचना और प्रक्रिया होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए यदि हमें भाषा की रक्षा करने की आवश्यकता है। मैं भाषा की जड़ों को और अधिक समझने और जीभ की रक्षा के लिए भाषा को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं।

महान गणितज्ञ एवं खगोलभौतिकीविद् हिप्पार्कस की जीवनी

विजय गर्ग

प्रारंभिक जीवन और कार्य

हिप्पार्कस, जिसे हिप्पार्कोस के नाम से जाना जाता है, एक यूनानी गणितज्ञ था जिसका जन्म 190 ईसा पूर्व में हुआ था। हिप्पार्कस के जीवन के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि उसका जन्म स्थान बिथिनिया में निकिया था जो आधुनिक तुर्की है। सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों और खगोलविदों में से एक होने के बावजूद, उनके काम का विवरण बहुत कम है, सबसे निश्चित रूप से जीवित टुकड़ा तीसरी शताब्दी की अराटस की एक कविता पर उनकी टिप्पणी है, 'यूडोक्सस और अराटस के फेनोमेना पर टिप्पणी'। इसके अलावा उनके योगदान की सूची में प्रकाशिकी और अंकगणित पर उनकी किताबें, भूगोल और ज्योतिष से संबंधित लेख और 'ऑन ऑब्जेक्ट्स कैरीड डाउन बाई देयर वेट' नामक ग्रंथ शामिल हैं। उनके अधिकांश खगोलीय कार्यों को दूसरी शताब्दी ईस्वी में टॉलेमी द्वारा लिखित 'अल्मागेस्ट' से जाना जाता है, जहां उन्होंने हिप्पार्कस के ज्ञान को अपने खगोलीय सिद्धांतों के आधार के रूप में इस्तेमाल किया था।

माना जाता है कि खगोल विज्ञान में उनका योगदान क्षेत्र के आधुनिक अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण उपयोग का है। सूर्यकेंद्रित प्रणाली की गणना करने वाले पहले व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि उनकी गणना के अनुसार कक्षाएँ वास्तव में गोलाकार नहीं थीं जैसा कि उस समय के विज्ञान की मान्यता थी। हिप्पार्कस ने 'डायोपट्रा' नामक उपकरण का उपयोग करके 147 से 127 ईसा पूर्व के समय के दौरान तारों का अवलोकन किया था। कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि वह एक खगोलीय उपकरण 'प्लानिस्फेरिक एस्ट्रोलैब' के आविष्कारक थे। यह कोई और नहीं बल्कि हिप्पार्कस ही था जिसने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जैसे कि एक वर्ष की लंबाई क्या है

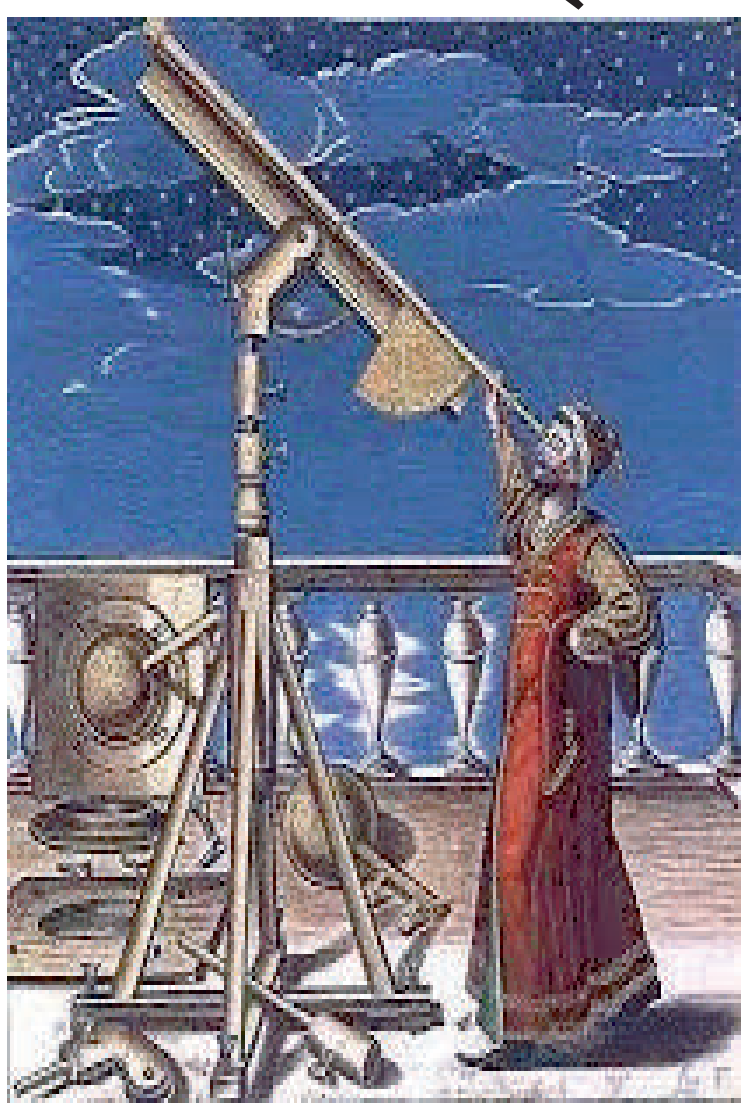

और चंद्र दूरी क्या है। उत्तर खोजने के लिए उत्सुक, हिप्पार्कस ने कई गणनाओं और तकनीकों का उपयोग करके सौर और चंद्र गति और उनकी कक्षाओं का व्यापक अध्ययन किया। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा दोनों की दूरी और आकार भी निर्धारित किया।

विषुव की खोज

हिप्पार्कस 'विषुव' की पूर्वता की खोज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। विषुव एक शब्द है जिसका उपयोग उस समय का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब सूर्य का केंद्र पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समान तल पर होता है। अपने स्वयं के अवलोकनों को अन्य खगोलविदों विशेष रूप से एरिस्टार्चस, मेटन और एक्टेमॉन द्वारा किए गए अवलोकनों के साथ मिलाकर, उन्होंने पूर्वता की मात्रा की गणना की और इस डेटा का उपयोग करके उष्णकटिबंधीय वर्ष की लंबाई पर भी विचार-विमर्श किया।

अन्य कार्य

कुछ गणितज्ञ हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का संस्थापक होने का श्रेय देते हैं। हम जानते हैं कि उनके पास एक त्रिकोणमिति तालिका थी जिसका उपयोग उन्होंने सौर और चंद्र कक्षाओं और उनकी विलक्षणता को प्राप्त करने के लिए किया था। पहली शताब्दी के अलेक्जेंड्रिया के मेनेलॉस के पाठ से संकेत मिलता है कि हिप्पार्कस गोलाकार त्रिकोणमिति से परिचित था और इसका उपयोग चंद्र लंबन और 'एक्लिप्टिक' (आकाशीय क्षेत्र पर सूर्य का पथ) के उदय और अस्त बिंदुओं की गणना के लिए किया जाता था।

मृत्यु और मान्यता

हिप्पार्कस के कार्यों को आज व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और उनके योगदान को याद करते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उच्च परिशुद्धता लंबन संग्रहण उपग्रह को 'HiPParCoS' नाम दिया गया था। एक चंद्र क्रेटर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है और क्षुद्रग्रह '4000 हिप्पार्कस' भी उनके नाम पर है। लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया की एक वेधशाला ने उन्हें छह महानतम खगोलविदों में से एक के रूप में स्थान दिया है। ऐसा माना जाता है कि हिप्पार्कस की मृत्यु 120 ईसा पूर्व में हुई थी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार पंजाब

बेटी

पाँच साल की बेटी बाज़ार में गोल गप्पे खाने के लिए मचल गई। "किस भाव से दिए भाई?" पापा नें सवाल किया। "10 रूपये के 8 दिए हैं। गोल गप्पे वाले ने जवाब दिया पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महँगे हो गये है. जब वे खाया करते थे तब तो एक रुपये के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब मे हाथ डाला 15 रुपये बचे थे। बाकी रुपये घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है 10 रुपये तो बस किराए में लग जाने है। "नहीं भई 5 रुपये में 10 दो तो ठीक है वरना नही लेने।"

यह सुनकर बेटी नें मुँह फुला लिया "अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महँगे। " पापा के माथे पर लकीरें उभर आयीं "अरे खा लेने दो ना साहब" अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है कल को पराये घर चली गयी तो पता नहीं ऐसे मचल पायेगी या नहीं. तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गयी

जिसकी शादी उसने तीन साल पहले एक खाते -पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था

दो साल तक वह मुट्ठी भरभर के रुपये उनके मुँह में ठूँसता रहा पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया .

और अंत में एक दिन सीढियों से गिर कर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुँची.

आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आये..? और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएँ पूरी कर दे

पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है. "दे दूँ क्या बाबूजी

गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी

"रुको भाई दो मिनिट . पापा पास ही पंसारी की दुकान थी उस पर गए जहाँ से जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई पाँच किलो चीनी में से एक किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब मे बढ़ गए।

फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबायी आँखें पोंछते हुए कहा अब खिलादे भाई। हाँ तीखा जरा कम डालना। मेरी बिटिया बहुत नाजुक है. सुनकर पाँच वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कस कर पकड़ लिया।

जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करे,...

क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाये या ना हो पाये ।

ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं.

सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊँगी पापा से ये मांगूंगी बहन से ये कहूँगी भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करुँगी

लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती है किसी से कुछ भी नहीं बोलती.

बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है। बहुत बहुत खुश होती है। भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल सब..

क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में एक अलग ही कशिश होती है मायके में.. ससुराल में कितना भी प्यार मिले..

माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियां.

ससुराल में कितना भी रोएँ पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां.

क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है रुला देता है..

कितनी अजीब है ये बेटियां कितनी नटखट है ये बेटियां भगवान की अनमोल देन हैं ये बेटियां

हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें उन्हें कभी भी न रुलाये क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार जोड़ती है दो रिश्तों को साथ लाती है। अपने प्यार और मुस्कान से।

हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा.... भले ही हो वो मायके में या ससुराल में।

खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं,

उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें क्यों की वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता की छोड़ कर आपके साथ पूरी ज़िन्दगी बीताने आयी है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आप से हैं।

विजय गर्ग

आपके पास है असली सोना? एक नंबर से चल जाएगा पता

परिवहन विशेष न्यूज

गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। जब भी बाजार में सोने की डिमांड बढ़ जाती है तो कई लोग इस मौके की तलाश में नकली सोना बेचते हैं। ऐसे में इस तरह के नकली सोने की धोखाधड़ी से बचें रहने के लिए आपको सोने की जांच करनी जरूरी है। आप गोल्ड ज्वैलरी पर छपे Hallmark Unique Identification No. के जरिये चेक कर सकते हैं।

नई दिल्ली। जैसे-जैसे दिवाली का त्योहार करीब आ रहा है, वैसे-वैसे सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। आज वायदा कारोबार में सोना 78,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 96,758 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस फेस्टिव सीजन गोल्ड और चांदी के दाम में शानदार तेजी आई।

भारत में सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। लोग त्योहार या शादी के सीजन में सोना खरीदना पसंद करते हैं। वैसे भी गोल्ड और सिल्वर निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। ऐसे में जहां सोने की कीमतों में तेजी आती है तो दूसरी तरफ कई लोग असली सोने के नाम पर नकली सोना बेचते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको हमेशा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके पास असली सोना है या नहीं इसकी जांच आप बड़ी आसानी से एक नंबर के जरिये कर सकते हैं।

सोने की जांच कैसे करें

हम जब भी कोई सामान की खरीदारी करते हैं को हमें काफी सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, आज के समय में कई तरह के धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको विश्वसनीय और रजिस्टर्ड ज्वैलर्स से ही खरीदना चाहिए। प्योर गोल्ड पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क लगा होता है। हॉलमार्क बताता है कि आप जो गोल्ड ज्वैलरी खरीद रहे हैं वह प्योर है।

अब लोगों के मन में सवाल आता है कि कई सुनार जवैलरी पर नकली हॉलमार्क भी छाप सकते हैं। अगर आपको कभी संदेह होता है कि ज्वैलरी पर छपा हॉलमार्क नकली या गलत है तो आप हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) के जरिये भी ज्वैलरी की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। BIS के अनुसार ज्वैलरी पर हॉलमार्क के साथ एक यूनिक नंबर भी छपा होता है।

अगर आप ध्यान से अपने गोल्ड ज्वैलरी देखें तो उस पर AZ4524 जैसे कोई नंबर प्रिंट होगा। इस नंबर के जरिये गोल्ड प्योरिटी की जांच की जा सकती है। इस नंबर में कैरेट और गोल्ड प्योरिटी की जानकारी होती है। वैसे सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से तय होता है। गोल्ड ज्वैलरी के 22 कैरेट या फिर उससे कम कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है।

इंडिगो और बंधन बैंक ने जारी किये तिमाही नतीजे, ऐसी रही कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

बाजार बंद होने के बाद इंडिगो और बंधन बैंक ने जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान किया। दोनों ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी दी। बता दें वर्तमान में इंडिगो और बंधन बैंक घाटे का सामना कर रहे हैं। हम आपको इस आर्टिकल में दोनों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टॉक की डिटेल्स देंगे। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। कई कंपनियों ने जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये और कई कंपनियों अभी नतीजों का एलान करेगी। आज बाजार बंद होने के बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और बंधन बैंक ने तिमाही नतीजे जारी किया।

हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि सितंबर तिमाही में इंडिगो और बंधन बैंक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा।

इंडिगो दूसरी तिमाही नतीजा

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बताया सितंबर तिमाही में उसे 986.7 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है। यह घाटा विमानों के खड़े होने और उच्च ईंधन लागत के कारण हुआ है। एयरलाइन ने प्रेस रिलीज में कहा कि पिछले साल उसे समान तिमाही में 188.9 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था।

इंडिगो ने अपने एयरलाइन की वृद्धि और विस्तार को जारी रखा क्यों सितंबर तिमाही में इंडिगो का राजस्व 14.6 फीसदी बढ़कर 17,800 करोड़ रुपये हो गया।

पीटर एल्बर्स ने आगे कहा कि ग्राउंडेड विमानों की संख्या और संबंधित लागत कम होने लगी है। सितंबर तिमाही में इंडिगो का ईंधन लागत 12.8 फीसदी बढ़कर 6,605.2 करोड़ रुपये हो गया। इंडिगो के शेयर (Indigo Share Price) 146.15 रुपये या 3.23 फीसदी की गिरावट के साथ 4,373.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। बंधन बैंक ने बताया सितंबर तिमाही में बैंक का नेट लॉस 30 फीसदी की वृद्धि के साथ 937 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 721 करोड़ रुपये रहा।

माइक्रोसौफ्ट के सीईओ को मिला 63 फीसदी का सैलरी हाइक

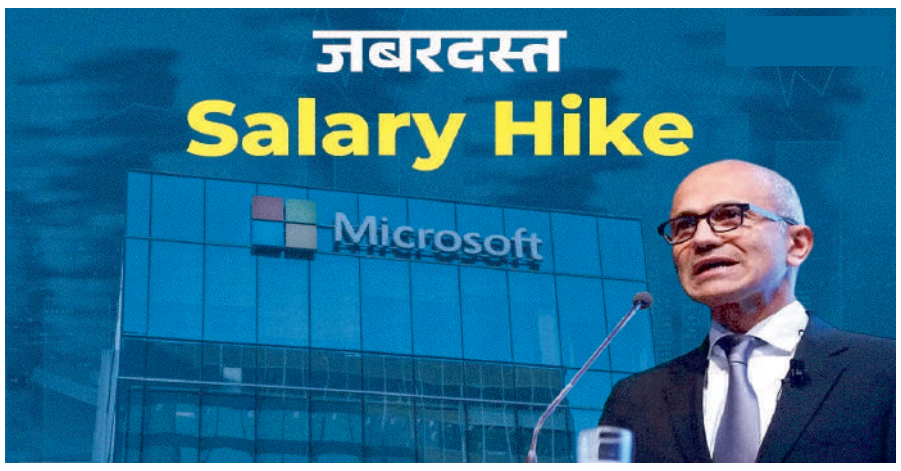

Microsoft के CEO Satya Nadella भारतीय मूल के हैं। हाल ही में इनकी सैलरी में शानदार इजाफा हुआ है। इस इजाफा के बाद अब इनका सैलरी पैकेज में करोड़ों में हो गया है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में आई शानदार तेजी और बाजार में मजबूत स्थिति के कारण सत्या नडेला की सैलरी में बढ़ोतरी हुई। पढें पूरी खबर..

नई दिल्ली। जहां एक तरफ कई आईटी कंपनियां छंटनी (IT Layoff) कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ Microsoft के CEO Satya Nadella के लिए खुशखबरी आई है। हाल ही में उनकी सैलरी हाइक हुई, जिसके बाद उनके सैलरी पैकेज (Satya Nadella Salary Package) का चर्चा हो रही है।

कितनी बढ़ी सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल सत्या नडेला की सैलरी में 63 फीसदी की हाइक हुई है। इस हाइक के बाद उनका पैकेज काफी बड़ा हो गया है। अब उनकी सैलरी 79.1 मिलियन डॉलर (करीब 665 करोड़ रुपये) हो गई है। नडेला की सैलरी में हुए इतने जबरदस्त इजाफा की वजह माइक्रोसॉफ्ट के शेयर (Microsoft Share) है। जी हां, पिछले कुछ समय से आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बाद स्टॉक अवॉर्ड के तहत इनकी सैलरी में वृद्धि की गई।

यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा है कि माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाने में सत्या नडेला का अहम योगदान है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट और OpenAI में निवेश किया। इसके बाद कंपनी की स्थिति बाजार में काफी मजबूत रही। इसके बाद नडेला की स्टॉक-बेस्ड इनकम में भी इजाफा हुआ।

AI से हुआ सबसे ज्यादा फायदा

माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसके शेयर 31.2 फीसदी तक बढ़े हैं। स्टॉक में आई इस तेजी का श्रेय एआई को जाता है। कंपनी जेनेरेटिव AI की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिससे कंपनी को फायदा हो रहा है।

सैलरी में इजाफा होने के बावजूद नडेला ने कैश सैलरी को कम करने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी इश्यू के कारण यह रिक्वेस्ट किया है।

कितनी है एक दिन की इनकम

सत्या नडेला का सैलरी पैकेज 79.1 मिलियन डॉलर (करीब 6,65,03,05,740 रुपये) है। ऐसे में अगर उनकी एक दिन की सैलरी लगभग 18220015 रुपये (लगभग 1.8 करोड़ रुपये) है।

98 फीसदी गिरा तेल कंपनी का मुनाफा, तिमाही नतीजे जारी होने के बाद क्या है स्टॉक का हाल

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने दूसरी तिमाही नतीजे जारी कर दिये। कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल मुनाफा 98 फीसदी गिर गया। इसके अलावा कंपनी की कमाई में भी गिरावट आई है। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद कंपनी के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। आइए कंपनी के तिमाही नतीजे पर नजर डालते हैं।

नई दिल्ली। राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने चालू कारोबारी साल के दूसरे तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। इस तिमाही नतीजे (HPCL Q2 Result) में कंपनी ने अपने वित्तीय स्थिति के बारे में बताया।

कैसी है कंपनी की वित्तीय स्थिति

एचपीसीएल ने बताया कि दूसरी तिमाही में उनके मुनाफे में 98 फीसदी की भारी गिरावट आई है। यह गिरावट राफाइनरी मार्जिन और मार्केटिंग मार्जिन कम होने की वजह से आई है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी को 5,826.96 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं, इस साल कंपनी को 142.67 करोड़ रुपये का ही मुनाफा हुआ है।

स्टॉक फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई से सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट के साथ इनकम में भी गिरावट आई। वहीं, जुलाई-सितंबर 2024 में डाउनस्ट्रीम ईंधन खुदरा कारोबार से प्री-टैक्स कमाई 6,984.60 करोड़ रुपये से घटकर 1,285.96 करोड़ रुपये हो गई।

क्यों घाटे में तेल कंपनियां

वर्तमान में देश की मुख्य तेल कंपनियां घाटे का सामना कर रही है। यह घाटे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव न होने की वजह से हो रहा है। हालांकि, पिछले साल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बावजूद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने लाभ कमाया था। वहीं, बीपीसीएल के साथ दो अन्य तेल कंपनियों ने घाटे की वजह पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती को ठहराया।

बता दें कि इस साल आम चुनाव से पहले सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों में तेदी और मार्जिन में गिरावट की वजह से भी तेल कंपनियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी और अन्य राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) - ने पिछले साल लागत में गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बनाए रखने से असाधारण लाभ कमाया था।

बीपीसीएल और अन्य दो खुदरा विक्रेताओं को पिछले साल हुए घाटे से उबरने के नाम पर कीमतों में कटौती को उचित ठहराया गया था, जब उन्होंने लागत में वृद्धि के बावजूद खुदरा कीमतें नहीं बढ़ाई थीं।

आम चुनावों की घोषणा से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के साथ कीमतों में स्थिरता से होने वाला लाभ खत्म हो गया। इसके साथ ही अपेक्षाकृत स्थिर कच्चे तेल की कीमतों पर उत्पाद दरार या मार्जिन में गिरावट के कारण मुनाफे में गिरावट आई।

एचपीसीएल के शेयर का हाल

आज एचपीसीएल के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। करीब 2.30 बजे एचपीसीएल के शेयर (HPCL Share Price) 27.30 रुपये या 6.76 फीसदी की गिरावट के साथ 377.40 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में एचपीसीएल के शेयर ने 130.08 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। वहीं बीते छह महीने में एचपीसीएल के शेयर में 15.25 फीसदी की तेजी आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के वेबसाइट के अनुसार एचपीसीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन (HPCL M-Cap) 80,006.13 करोड़ रुपये है।

रतन टाटा ने अपनी वसीयत में पेटडॉग का भी रखा ध्यान

हाल ही में देश बड़े उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा का देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद उनकी वसीयत (Ratan Tata Will) सामने आई। इस वसीयत में उनके भाई-बहन बटलर के साथ पेटडॉग Tito का नाम भी शामिल है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय उद्योगपति के वसीयत में पेटडॉग के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। हाल ही में देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले रतन टाटा (Ratan Tata) का देहांत हुआ था। रतन टाटा ने अपने पीछे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ दी है। अब सवाल आता है कि उनकी इस संपत्ति का ध्यान कौन-रखेगा।

रतन टाटा के वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति में भाई जिमी टाटा, सौतेली बहनों शिरीन और डिएना जीजीभॉय, हाउस स्टाफ और अन्य लोगों के लिए काफी कुछ छोड़ा है। यहां तक कि उनकी वसीयत में पेटडॉग टीटो (Tito) के लिए भी प्रावधान है।

कौन-है टीटो के नए केयरटेकर

रतन टाटा ने पांच-छह साल पहले जर्मन शेफर्ड डॉग टीटो को गोद लिया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनको जानवरों से कितना प्यार था। अब रतन टाटा ने अपने वसीयत में टीटो की 'असीमित' देखभाल सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। यह भारत में पहली बार है जब किसी उद्योगपति के वसीयत में इस तरह का प्रावधान हो। विदेशों में इस तरह के प्रावधान सामान्य होते हैं पर भारत में यह काफी दुर्लभ है। माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय उद्योगपति ने अपने वसीयत में ऐसा प्रावधान किए हैं।

रतन टाटा के वसीयत के अनुसार टीटो की देखभाल की जिम्मेदारी रसोइए राजन शॉ को दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रतन टाटा के वसीयत में उनके बटलर सुब्बैया के लिए भी प्रावधान है। बता दें कि पिछले तीन दशकों से राजन शॉ और सुब्बैया रतन टाटा से जुड़े हैं।

शांतनु नायडू को क्या मिला

रतन टाटा के वसीयत में एग्जीक्यूटिव एसिसटेंट शांतनु नायडू का नाम भी है। रतन टाटा ने नायडू के वेंचर गुडफेलो (GoodFellow) में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। इसके अलावा उन्होंने नायडू के फॉरेन एजुकेशन के लिए लिया गया पर्सनल लोन (Personal Loan) भी माफ कर दिया। बता दें कि टाटा ग्रुप में चैरिटेबल ट्रस्ट्स के शेयरों को छोड़ने की परंपरा है, रतन टाटा ने भी इस परंपरा को जारी रखा।

RTEF को ट्रांसफर हुई टाटा ग्रुप के शेयर

रतन टाटा की हिस्सेदारी अब रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) को ट्रांसफर की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब RTEF के चेयरमैन टाटा संस के प्रमुख एन चंद्रशेखरन बन सकते हैं।

गोल्ड ज्वैलरी खरीदने से पहले जानें कैसे तय होती है कीमत, ज्वैलर्स कौन-से कैलकुलेशन का करते हैं इस्तेमाल

सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जब भी हम कोई गोल्ड ज्वैलरी खरीदते हैं तो हमार मन में सवाल आता है कि आखिर इसकी कीमत कैसे तय होती है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि ज्वैलरी की कीमत तय करने के लिए कौन-सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है।

नई दिल्ली। अगले हफ्ते दिवाली का त्योहार है। ऐसे में सभी बाजार में रौनक छाई हुई है। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन सोना खरीदना काफा शुभ माना जाता है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर लोग गोल्ड ज्वैलरी खरीदते हैं। ऐसे में सोने की डिमांड बढ़ जाने से इनकी कीमतों में भी इजाफा होता है। अगर आप भी इस साल गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो आपको सोने की कीमतों का ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि सोने की कीमत रोज अपडेट होती है।

इसके अलावा जो भी आप ज्वैलरी खरदीते हैं उसकी कीमत सुनार तय करता है। अब सवाल आता है कि सुनार किसी भी ज्वैलरी की कीमत कैसे तय करता है? क्या ज्वैलरी की कीमत तय करने के लिए कोई फॉर्मूला है? हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे।

इन चीजों पर निर्भर करती है सोने की कीमत

सुनार अपनी खरीद के बाद ही आभूषण की कीमत तय करता है। इसके अलावा आप कौन-से कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं यह भी निर्भर करता है। बता दें कि 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड के रेट अलग हैं। वैसे तो ज्वैलरी के लिए 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है। अब गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewellery) बनाने में इन कैरेट के गोल्ड का कितना इस्तेमाल हुआ है इसको नापने के बाद ही कीमत तय होती है।

कैसे तय होती है गोल्ड ज्वैलरी की कीमत गोल्ड ज्वैलरी की कीमत तय करने के लिए सुनार एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्वैलरी के वजन को गोल्ड की कीमत से गुणा किया जाता है। इसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज को जोड़ा जाता है और अंत में 3 फीसदी जीएसटी (GST) को एड किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि 20 कैरेट गोल्ड की कीमत 68,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है और किसी ज्वैलरी का वजन 35 ग्राम है।

जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोला जॉब मार्केट, हर साल 90 हजार वीजा देने का एलान

जर्मनी में नौकरी करने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। जर्मन सरकार ने भारतीयों को दिए जाने वाले वर्क वीजा की संख्या में बड़ा इजाफा करते हुए इसे 90 हजार हर साल करने का एलान किया है। अभी तक इस श्रेणी में 20 हजार भारतीयों को वीजा मिलता था। इसका एक अहम कारण जर्मनी की अपनी खुद की जरूरत भी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

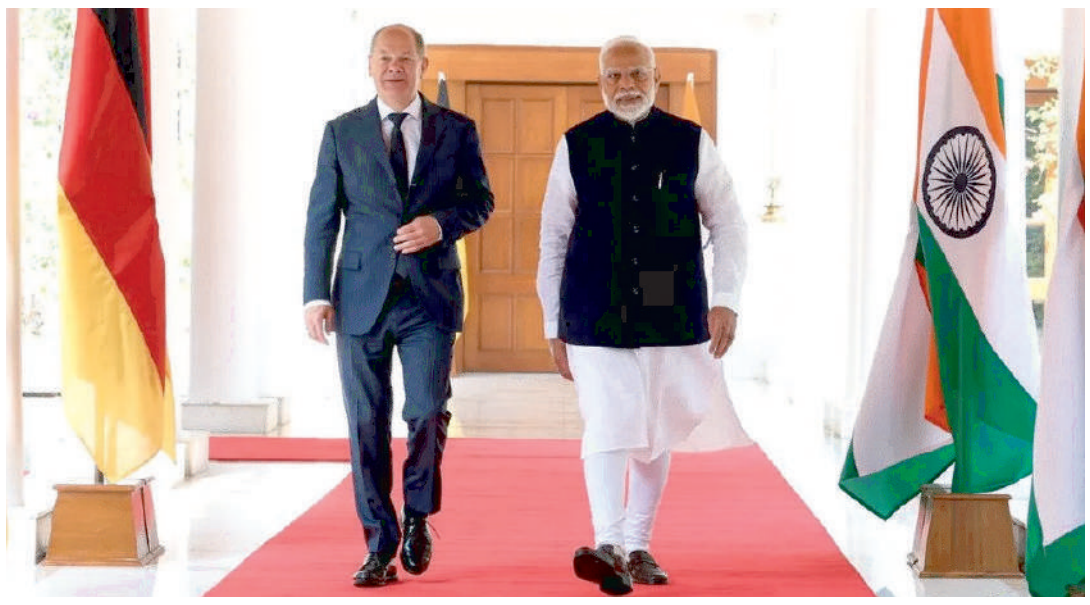

नई दिल्ली। यूरोप में आर्थिक तौर पर सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी ने अपने जॉब मार्केट को भारतीयों के लिए खोल दिया है। जर्मन सरकार ने फैसला किया है कि वह हर साल 90 हजार भारतीयों को काम करने का वीजा देगी। अभी तक इस श्रेणी में 20 हजार भारतीयों को वीजा मिलता था।

वीजा देने की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाई भी जा सकती है। इस बात की जानकारी भारत के दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दी। शुक्रवार को उनकी पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात हुई और द्विपक्षीय संबंधों के तमाम आयामों पर बात हुई। पीएम मोदी ने जर्मनी की इस घोषणा की जानकारी दी और इसका स्वागत किया।

मजबूत स्थिति में है जर्मनी

जर्मन व्यवसायों के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन (एपीके- 2024) में पीएम मोदी ने कहा कि जर्मनी ने प्रशिक्षित भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या, 20 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। गौरतलब है कि जर्मनी ना सिर्फ यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि इसकी आर्थिक विकास दर की संभावनाएं भी यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले सबसे अच्छी है।

यूरोप के दूसरे देश जहां अवैध प्रवासी समस्या और आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं जर्मनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसे तेज आर्थिक विकास दर की रफ्तार बनाये रखने के लिए श्रम चाहिए, जिसकी पूर्ति अभी सिर्फ भारत करने की स्थिति में है। चासंलर शोल्ज भारत व जर्मनी के रिश्तों को मजबूत करने को खासी प्राथमिकता पर लेते हैं। उनकी गठबंधन सरकार की सरकार चलाने संबंधी प्रपत्र में भारत के खास तौर पर किया गया है।

भारत को लेकर जर्मनी का विशेष प्रपत्र

भारत आने से पहले शोल्ज की कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया नाम से एक प्रपत्र को मंजूरी दी है। भारत सिर्फ दूसरा देश है, जिसके साथ संबंधों को लेकर विशेष प्रपत्र जर्मनी ने जारी किया है। इस प्रपत्र में भारत के सकुशल व पेशेवर कामगारों को जर्मनी में अवसर देने का विस्तार से जिक्र किया गया है। जर्मनी पिछले चार-पांच वर्षों से भारतीयों कामगारों को आकर्षित कर रहा है। इस वजह से वहां भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या दोगुनी होकर 2.50 लाख हो चुकी है।

इस पर चांसलर शोल्ज ने कहा, 'जर्मनी के विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। पिछले साल ही 23 हजार भारतीय पेशेवरों ने जर्मनी में काम करना शुरू किया है।' उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों व कामगारों को शीघ्रता से वीजा देने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, जर्मनी अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण रखेगा और सिर्फ पढ़े-लिखे कामगारों को आमंत्रित करेगा।

जर्मनी को चाहिए हर साल चार लाख पेशेवर

जर्मनी के श्रम व सामाजिक मामलों के मंत्री हुबेर्टस हील ने बताया, 'जर्मनी को हर साल चार लाख पेशेवर कामगार चाहिए और इसमें से बड़ी संख्या भारत से ली जाएगी। भारतीय कामगारों को पूरी दुनिया में इज्जत है और जर्मनी का अनुभव बहुत बेहतर है।' गुरुवार को भारत और जर्मनी के बीच आठ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें श्रम व रोजगार को लेकर भी है।

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई ने सरायकेला सीट से नामांकन भरा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

सरायकेला, झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होट सीट सरायकेला -51 (एसटी) के लिये विधानसभा चुनाव हेतु नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके साथ सरायकेला सीट से उसी चंपाई सोरेन से दो बार मात खाये गणेश महाली ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नामांकन दाखिल किया।

खंरसावा सीट के लिए भी जिला परिषद अध्यक्ष सोना राम विरूवा ने भी पर्चा भरा।

झारखंड मविधानसभा चुनाव के आज प्रथम चरण के अंतिम दिन काफी गहमा गहमी रही। जहां सूवे के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के विधायक चंपाई सोरेन ने अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में ताम झाम के साथ पहुंचकर पर्चे भरे। चंपाई सोरेन उन नेताओं मे से आते जो द्वितीय चरण झारखंड आंदोलन के पहले के उपज है। चंपाई ने इसी वर्ष हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा कस्टडी में लेने के बाद 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी।

चंपाई सोरेन ने 1991 में सर्वप्रथम सरायकेला सीट से चुनाव लडा था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबु सोरेन गुट एवं सुरज मंडल गुट दो गुटों में जे एम एम विभाजित हुआ तथा कृष्ण मार्डी इसी सीट से विधायक के बाद सिंहभूम सांसद बने थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्रित्व काल के चर्चित सांसद रिश्वत कांड समय में। चंपाई सोरेन 1991से 2000तक झामुमो के विधायक रहने के बाद 2000मे चुनाव भाजपा से ही हार गये थे। इसके बाद 2005 से आज 2024 तक वे इसी सीट से विधायक, मंत्री बनते रहे हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवू सोरेन के बाद सबसे पुराने जे एम एम नेता रहे है ,तथा राज्य का सातवां मुख्यमंत्री के रूप में पांच मह की एक छोटी सी अवधी के लिए मुख्यमंत्री भी बने। सरायकेला उनकी एवं जे एम एम की पारंपरिक सीट कही जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर भाजपा के गृह विभिषणों को नजर अंदाज की जाय तो ! परन्तु आज भगवा धारी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर पहली बार वे सीधे मैदान में नवकलेवर के साथ उतर रहे हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी के तौर पर सरायकेला सीट से 2 वार हारने वाले गणेश महाली को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चुनाव में नामांकन के साथ मैदान में उतरा गया है । उधर खरसावां सीट से विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार सोना राम पहली बार चुनाव लड रहे हैं

तूफान ने दस्तक दी, हवाई यातायात सामान्य हो गया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर् : तूफान ने दस्तक दी, हवाई यातायात सामान्य हो गया। शुक्रवार को चक्रवात दाना के टकराने के बाद भुवनेश्वर में सामान्य उड़ान संचालन की खबरें आई हैं।सुबह 8 बजे से हवाई यातायात पहले की तरह बहाल होने की जानकारी एयरपोर्ट के निदेशक ने दी। हालांकि, तूफान के कारण कल शाम 5 बजे से हवाई यातायात बंद कर दिया गया था। बताया गया है कि तूफान के दस्तक देने के बाद तय समय से एक घंटे पहले ही हवाई यातायात सामान्य हो गया है। गौरतलब है कि चक्रवात दाना भीषण रूप धारण कर जमीन से टकरा चुका है और तट पर तूफान चल रहा है। तूफान का केंद्र हबलिख्ती, केंद्रपाड़ा आंतरिक प्रकृति पार्क के पास पहुंचा। मध्य रात्रि में 1:30 से 3:30 के बीच तूफान आया। 5 दिनों तक भारी बारिश होती रही। आज सुबह 8 बजे से हवाई यातायात सामान्य हो गया । तूफान के कारण हवाई यातायात निलंबित कर दिया गया। कल शाम 5 बजे से हवाई यातायात बंद था एयरपोर्ट निदेशक को सूचना दी।

चेन्नई के स्कूल में हादसा, गैस लीक होने से 30 से ज्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ी; अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक स्कूल में शुक्रवार को एक साथ कई छात्र बीमार हो गए। आंखों में जलन और चक्कर आने की शिकायत के बाद इन बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

चेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक स्कूल में शुक्रवार को एक साथ 30 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। आंखों में जलन और चक्कर आने की शिकायत के बाद इन बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है, इन छात्रों की हालत ठीक है। वहीं एनडीआरएफ के कमांडर एके चौहान ने इस मामले में कहा हैं, ₹फिलहाल, मैं सटीक कारण नहीं बता सकता। हमें अभी तक सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है। हमारी टीम ने आकर स्थिति का आकलन किया, सब कुछ सामान्य है, हमें किसी गैस की गंध नहीं आई...₹

'बेटी को सांस लेने में हुई थी परेशानी'

वहीं इस मामले में एक छात्रा की मां का कहना है, ₹दो दिन पहले मेरी बेटी ने सांस लेने में कठिनाई और उल्टी की शिकायत की थी। उसने कल भी यही शिकायत की थी। आज उसे उल्टी हुई और चक्कर आ रहा था। लेकिन कुछ शिक्षकों ने कहा कि ऐसा व्यवहार न करें।"

'स्कूल ने नहीं दी कोई जानकारी'

उन्होंने ये भी कहा, "स्कूल ने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। फिर हमारी बेटी को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर हम उसे एक निजी अस्पताल में ले गए। अभी तक स्कूल प्रशासन ने हमें कुछ नहीं बताया है।₹

कहां से लीक हुई थी गैस?

हालांकि, अन्य रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि धुआं पास की किसी रासायनिक सुविधा से आया हो सकता है। अधिक खतरों से बचने के लिए, अधिकारी इस मुद्दे पर नजर रख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि रिसाव कहां से हुआ।

यह घटना तमिलनाडु के होसुर में एक कॉर्पोरेशन मिडिल स्कूल में लगभग 100 बच्चों के दोपहर के भोजन के बाद अचानक बीमार पड़ने के कुछ दिनों बाद हुई है।

बड़खल चौक से सेक्टर 29 फरीदाबाद रोड पर भयंकर दुर्घटना, स्कूल की दो टीचर चपेट में

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद, दोपहर करीब 2 बजे बड़खल चौक से सेक्टर 29 बायपास रोड पर स्थित सेक्टर 29 के टी-प्वाइंट पर एक भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें एवरग्रीन स्कूल की दो टीचर गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना संजय मेडिकल स्टोर के सामने हुई, जिसमें से एक मैडम की हालत नाजुक बताई जा रही है।

इस हादसे ने एक बार फिर से सेक्टर 29 आरडब्ल्यूए (हुडा) की लंबी समय से चल रही रेड लाइट लगाने की मांग को लेकर प्रशासनिक उदासीनता को उजागर कर दिया है।

आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी, श्री सुबोध नागपाल, ने कई बार लिखित में स्मार्ट सिटी, समाधान शिविर में डीसी साहब, और पुलिस विभाग को पत्र देकर इस स्थान पर रेड लाइट लगाने की अपील की है। इसके बावजूद, अभी तक किसी भी विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टी-प्वाइंट पर ट्रैफिक की स्थिति बेहद खतरनाक है और दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। वे प्रशासन से जल्द से जल्द रेड लाइट और अन्य सुरक्षा उपाय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूनी सडक़ों का अधूरापन

हम हवा में तीर चलाने और अधूरे सपनों की सहायता से अपने जीवन की उजड़ी हुई बगिया को एक शालीमार बाग बना देने की कल्पना करने में पारंगत हो चुके हैं। लेकिन केवल कल्पनाओं की उड़ान अगर हवाई घोड़े होती तो आज उस पर सभी मरभुक्खे सवार होकर अपने लिए नंदन कानन रच चुके होते। लेकिन बागों में घास की मखमली रविशों का बिछ जाना एक वास्तविकता तो क्या, हमारे भूखे-प्यासे सपनों में आने से भी कतराने लगी। यहां तो अब बिखरी है वही कैक्टस नुमा दिन रात चुभती असलीयत और एक ऐसी पंगु और शर्मसार कर देने वाली इच्छा कि इस बार खूब सर्दी पड़ेगी और हमारे घरों के दरवाजे खटखटा कर बीमारियों के पैगाम बांटेंगे। आज से सदी पहले दुनिया में एक बार महामंदी तिर आई। तब बेकारों के हुजूम भूख से पागल होकर सडक़ों पर तोडफ़ोड़ करते घूम रहे थे और फ्रांस की एक राजकुमारी ने अपने मुसाहिबों से पूछा, 'भूख, भई यह क्या होती है भूख।' 'एक कचोटती हुई आग जो अगर रोटी-पानी से शांत न हो तो आदमी इस दुनिया ये फानी से कूच कर जाता है।' जवाब मिला। राजकुमारी घबराई। उसे अपने खिलते हुए बागीचों, स्वर्णिम राजमहल में गद्दों पर रोटी के बिना भूख से तड़प कर मरते आदमियों की कल्पना भयावह लगी। उसे वहां नींद नहीं आई। तब उसने मासूमियत से सवाल किया, 'अरे रोटी नहीं है तो ये लोग केक और पेस्ट्री खाकर अपनी भूख क्यों नहीं मिटा लेते।' लेकिन रोटी से लेकर केक और पेस्ट्री खाने पर एकाधिकार तो ऊंची अटारियों ने किया हुआ है। तब भी कर रखा था।

आज सदी बीतने के बाद ऐसे ही दिन फिर आए तो पता लगा कि इस बीच कुछ भी नहीं बदला। सबको रोजी रोटी देने का अधिकार दे देने के बड़बोले भाषणों के बावजूद राजशाही चली गई। तब भूखा आदमी राजा-महाराजाओं का चंवर झुलाता था। उनके राजसी खाने की मेज से केक और पेस्ट्री के टुकड़ों की अपने लिए गिरने की कल्पना करता था। आज लोकशाही आ गई, नेताओं की गलदश्रु भावुकता से सने भाषणों से उनके लिए बीस लाख करोड़ रुपए की आर्थिक अनुकम्पा बरसती है। 'हर माल मिलेगा बारह आना' की तरह 'कर्ज ले लो, सस्ते कर्ज ले लो' की बोली उभरती है। लेकिन कुछ न समझे खुदा करे कोई। घोषणाएं हवाई हो गईं। घोड़े जिनकी कमर पहले ही भारी कर्ज के बोझ से टूट गई थी, उन्हें नया कर्ज उठा कर ताजा दम किसी नई रेस में भागने की सीटी बजाई जा रही है। घोड़े कैसे भागते? लेकिन उन्हें बची केक, पेस्ट्री खाने जैसे ये सस्ते कर्जे नहीं चाहिए। पहले उनके पेट में जलती भूख की आग को तुष्ट कर दो। भूखे को रोटी नहीं, बेकार को काम नहीं, दुकानें खोल दीं उन पर ग्राहक नहीं, बसें-रेलगाडियां चला दीं, उन पर मुसाफिर सवार होते घबराते हैं। पहले दम तोड़ते सपनों की तरह दाहक्रिया हो जाने दो। उनकी लाशों के अंबार पर ही नई जिंदगी के फूल रोपने की चाह न करो। अब इस माहौल में किसी नई प्रेम कविता की उम्मीद न करना। बहुत दिन पहले एक क्रांतिधर्मी कवयित्री दुनिया बदलने का अलख जगाती हुई बागी महफिलों में घूमती थी और नकियाये सुर में कविता पढ़ती, 'मेरा चुंबन, मेरा आलिंगन, सब मजदूरों के लिए है ताकि वे अपनी प्रताडना के प्रतिकार में निजाम को बदल दें।' निजाम बदलने की जरूरत तो आज भी है। इस बीच शोषण ने कई रूप ले लिए। अच्छे भले काम करते लोग अपने बच्चों को रूखी-सूखी दो जून की रोटी खिलाते थे। लोग चलते कर दिए। अब हाथ की कुदाल से लेकर कलम तक छिन जाने के बाद वे अपने आहत कदमों के साथ सडक़ें नाप रहे हैं। इस शोषक निजाम को बदल देने की इच्छा भला उनसे अधिक किसमें होगी? सोचता हूं अगर वह क्रांति समर्पित कवयित्री उन्हें प्रेरणा देने के लिए अपने चुंबन, आलिंगन उनसे बांटने आज आती तो क्या कोई इसे स्वीकार करता?

सुरेश सेठ

युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति

वर्तमान समय में भी देखने में आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स देखादेखी में अपने बच्चों की रुचि जाने बिना साइंस या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पर मजबूर करते हैं। राजस्थान के कोटा शहर को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों का हब माना जाता है, लेकिन वहां आत्महत्याएं हो रही हैं'

भारत में युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति केवल एक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में 1.71 लाख और 2023 में लगभग 2 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जो दुनिया में सबसे अधिक है। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि 41 फीसदी आत्महत्याएं 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा की जाती हैं। इसके पीछे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, आर्थिक चिंताएं, प्रेम संबंधों में असफलता, नशे की लत और घरेलू हिंसा जैसे कई जटिल कारण शामिल हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार देश में हर दिन 35 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स खुद की जान ले रहे हैं। यानी हर 40 मिनट में देश का एक स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है। स्टूडेंट सुसाइड की यह गिनती देश में किसानों की आत्महत्या से भी ज्यादा है। यह चौंकाने वाले आंकड़े आईसी-3 कॉन्फ्रेंस और एक्स्पो 2024 के दौरान जारी 'स्टूडेंट सुसाइड : एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया रिपोर्ट' में सामने आए हैं। आईसी-3 इंस्टीट्यूट एक नॉन-प्रॉफिट संस्थान है जो हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों पर अध्ययन करता है। यह रिपोर्ट एनसीआरबी के 2021 के डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में देश में 13089 छात्रों ने आत्महत्या की। वहीं, पिछले 10 सालों में करीब एक लाख छात्रों ने आत्महत्या की है।

पेशे के हिसाब से आत्महत्या की दर देखने पर पता चलता है कि दिहाड़ी मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों की आत्महत्या की दर क्रमशः 25.6 फीसदी और 9.7 फीसदी है। जबकि बेरोजगारों की आत्महत्या की दर 8.4 फीसदी है। हमारे देश में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य का बोझ अत्यधिक बढ़ रहा है। सफलता का दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं तथा व्यक्तिगत समस्याएं- जैसे करियर और रिश्तों की चुनौतियां, युवाओं को आत्महत्या के रास्ते पर धकेल रही हैं। इस संक्रमणकालीन अवस्था में, वे अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें अवसाद, एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर प्रमुख हैं। पारिवारिक उपेक्षा और सामाजिक दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को और भी गंभीर बना रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप हताशा और निराशा बढ़ रही है, और कई युवा नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस गंभीर स्थिति में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने युवाओं पर नजर रखनी चाहिए। उनसे संवाद करना चाहिए और उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हाल ही में, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसमें विशेषकर महिलाओं के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की घटनाओं में 15 फीसदी महिलाएं शामिल हैं, जिनके पीछे अवसाद और तनाव के कई बाहरी और घरेलू कारण हैं। साइबर बुलिंग भी युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। राज्य में भी आत्महत्या के मामलों की संख्या चिंताजनक है। 2020 से 2023 के बीच 3385 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से अधिकांश मामले दांपत्य जीवन में तनाव, वित्तीय चिंताएं, नशीले पदार्थों की लत, बेरोजगारी और पारिवारिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इस भीषण समस्या का समाधान एक बहुआयामी रणनीति के माध्यम से ही संभव है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और शिक्षा प्रणाली में सुधार शामिल हैं।

सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों को मिलकर काम करना होगा। युवाओं को यह बताना जरूरी है कि उनकी समस्याओं के समाधान मौजूद हैं और वे अकेले नहीं हैं। संवाद के माध्यम से युवाओं को समझाना और उन्हें स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। इसमें पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव कम करने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। अंततः, शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य बनाना भी महत्वपूर्ण है। कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित कर छात्रों को आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूक किया जा सकता है। एक सामूहिक प्रयास के तहत, सहानुभूति और समर्थन का माहौल बनाना युवाओं को अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करेगा। आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक ठोस और समर्पित रणनीति के माध्यम से ही हम युवाओं को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम सभी स्तरों पर सहयोग करें, तो हम इस संकट को समाप्त कर सकते हैं और युवाओं को एक स्वस्थ, सकारात्मक भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समर्थन दें, ताकि वे अपनी चुनौतियों का सामना कर सकें और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर बिना वजह का दवाव नहीं बनाना चाहिए।एक समय था जब समाज केवल साइंस या इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लोगों को तवज्जो देता था। वर्तमान समय में भी देखने में आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स देखादेखी में अपने बच्चों की रुचि जाने बिना साइंस या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पर मजबूर करते हैं। राजस्थान के कोटा शहर को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों का हब माना जाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोटा स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है। लेकिन इसका दूसरा स्याह पक्ष भी है। कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं! अब समय की जरूरत है कि पेरेंट्स बच्चों पर बिना वजह से दवाब न बनाएं और यह समझने का प्रयास करें कि सूचना के युग में हर विषय में स्कोप है, बशर्ते स्टूडेंट उसमें रुचि और महारत हासिल करे। ऐसी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम आत्महत्या की इस घातक प्रवृत्ति को रोक सकते हैं और एक सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं।

रमेश धवाला, पूर्व मंत्री

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023